उत्तरी कोरिया, क्रांतियां और पूंजीवादी पुनर्स्थापना

I

"...सामाजिक-जनवादी आंदोलन सारतः एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन है। इसका मतलब न सिर्फ यह है कि हमें अंधराष्ट्रवाद का मुकाबला करना चाहिए, बल्कि इसका मतलब यह भी है कि एक नये देश में शुरू होने वाला आंदोलन केवल उसी हालत में सफल हो सकता है, जब वह दूसरे देशों के अनुभव का उपयोग करे। इस अनुभव का उपयोग करने के लिए उसकी जानकारी रखना या नवीनतम प्रस्तावों की नकल कर लेना ही काफी नहीं है। इसके लिए जरूरत इस बात की है कि इस अनुभव को **आलोचनात्मक दृष्टि** से अंगीकार किया जाय और उसे **स्वतंत्र रूप** से परखा जाय। आधुनिक मजदूर आंदोलन कितना बढ़ चुका है और कितनी शाखाओं-प्रशाखाओं में फैल चुका है, इसका जिसे थोड़ा भी ज्ञान है, वह यह समझ लेगा कि इस काम को पूरा करने के लिए **सैद्धान्तिक शक्तियों तथा राजनीतिक (और साथ ही क्रांतिकारी) अनुभव के कितने विशाल संचित कोष** की आवश्यकता है।"

(लेनिन, क्या करें?, पृष्ठ-40, पैरा-2, हिन्दी अनुवाद, प्रगति प्रकाशन, दूसरा संस्करण, जोर हमारा)

उत्तर कोरिया या जनवादी जन गणतंत्र कोरिया (Democratic People's Republic Of Korea- DPRK) की बीसवीं सदी की सम्पूर्ण यात्रा का अध्ययन करते समय लेनिन का उपरोक्त कथन हमें आवश्यक दिशा निर्देश दे देता है।

बीसवीं सदी में कोरिया की यात्रा जापान का उपनिवेश (1910 में) बनने से शुरू होती है। कोरिया प्रायद्वीप 1910 से 1945 तक जापान के कब्जे में रहा। 1945 में कोरियाई प्रायद्वीप के विभाजन से दो देश अस्तित्व में आये। साम्राज्यवाद विरोधी-सामंतवाद विरोधी जनवादी क्रांति को सम्पन्न करने वाला उत्तरी कोरिया जो कि बाद के वर्षों में जनवादी जन गणतंत्र कोरिया के नाम से जाना गया। प्रायद्वीप के दक्षिणी हिस्से में अमेरिकी साम्राज्यवाद ने अपनी कठपुतली सरकार कायम की तथा उसे अपने नव उपनिवेश में तब्दील कर डाला। तब से दक्षिण कोरिया को कोरियाई गणतंत्र या रिपब्लिक ऑफ कोरिया (Republic of Korea-ROK) कहा जाने लगा। उत्तरी कोरिया ने साम्राज्यवाद-सामन्तवाद विरोधी जनवादी क्रांति को सम्पन्न करते हुए समाजवाद की स्थापना की ओर कदम उठाये। साठ के दशक में उत्तरी कोरिया समाजवाद के पथ से विचलित होने लगा। सत्तर के दशक में उत्तरी कोरिया में राजकीय-पूंजीवाद स्थापित हो गया। नब्बे के दशक में उत्तरी कोरिया ने खुले पूंजीवाद की ओर कई कदम बढ़ाये।

लेनिन का यह कथन कि सामाजिक-जनवादी आंदोलन (स्पष्टतः आज के संदर्भ में क्रांतिकारी कम्युनिस्ट आंदोलन) अपने सार में एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन है, उत्तरी कोरिया के संदर्भ में, दो भिन्न अर्थों में, अपनी पुष्टि करता है।

पहला, उत्तरी कोरिया की साम्राज्यवाद-सामन्तवाद विरोधी जनवादी क्रांति में अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट आंदोलन का प्रत्यक्ष और अभिन्न योगदान रहा है। पहले जापानी साम्राज्यवादियों और फिर अमेरिकी साम्राज्यवादियों को शिकस्त देने के लिए कोरियाई जनता तथा क्रांतिकारियों के साथ सोवियत संघ, चीन तथा कई देशों के कम्युनिस्ट और जनता कंधे से कंधा मिलाकर लड़े।

दूसरा अनुभव नकारात्मक है। यह 'महान बहस' के समय का है। अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट आंदोलन में नव संशोधनवादियों द्वारा डाली गयी फूट के समय कोरियाई कम्युनिस्टों ने अपने राष्ट्रीय हितों का ध्यान रखते हुए क्रांतिकारियों का साथ देने के बजाय तटस्थता का रुख अपनाया। किम इल-सुंग ने माओ का साथ देने के स्थान पर अपनी मध्यमार्गी स्थिति को मजबूत करने के लिए उसे सैद्धान्तिक जामा पहनाया। इस सैद्धान्तिक जामे ने उत्तरी कोरिया के नेताओं को राष्ट्रवादी भटकावों की ओर बढ़ाया तथा धीरे-धीरे सोवियत संशोधनवादियों तथा चीनी संशोधनवादियों के साथ ही खड़ा कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट आंदोलन में संशोधनवादी लाइन के खिलाफ चल रहे संघर्ष से किनाराकशी करके कोरियाई कम्युनिस्टों ने गैरमार्क्सवादी, राष्ट्रवाद और भाववाद से युक्त जूछे सिद्धान्त या किम इल-सुंगवाद को जन्म दिया। जूछे सिद्धान्त को किम इल-सुंगवाद का नाम किम इल-सुंग के 'ज्येष्ठ पुत्र' व उनके ही जीवनकाल में कोरियाई मजदूर पार्टी के जरनल सेक्रेटरी बने किम जांग-इल ने फरवरी 1974 में दिया।

लेनिन ने कम्युनिस्ट आन्दोलन के अनुभवों को आलोचनात्मक दृष्टि से अंगीकार करने को कहा है। यही चीज आज उत्तरी कोरिया की बीसवीं सदी की पूरी यात्रा पर लागू करने की जरूरत है।

एक अन्य चीज जिसे लेनिन के उपरोक्त उद्धरण में हमने रेखांकित करने की कोशिश की है वह यह है कि कम्युनिस्ट आंदोलन की शाखाओं व प्रशाखाओं का अध्ययन करते समय सैद्धान्तिक शक्तियों तथा क्रांतिकारी अनुभव के कितने विशाल संचित कोष की आवश्यकता है। आज स्थिति यह है कि हमारे देश में कम्युनिस्ट पार्टी तथा अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर कम्युनिस्ट इण्टरनेशनल या कॉमिंफार्म जैसी संस्थाओं का अभाव है।

स्वभावतः प्रस्तुत लेख की उपरोक्त कारणों से स्पष्ट सीमाएं बन जाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट आंदोलन के दस्तावेजों का अभाव उत्तरी कोरिया के अनुभव को आलोचनात्मक दृष्टि व स्वतंत्र रूप से परखने में बाधा पैदा करता है।

इन सीमाओं के बावजूद प्रस्तुत लेख में उत्तरी कोरिया की बीसवीं सदी की यात्रा का लेखा-जोखा लिया गया है और आवश्यक सबक निकाले गये हैं।

II
जापानी साम्राज्यवाद से मुक्ति और जनवादी क्रांति

1910 में जापानी साम्राज्यवादियों ने कोरिया को अपना उपनिवेश बना लिया था। जापानी साम्राज्यवादियों के कब्जे से पहले ही कोरिया को लेकर विभिन्न साम्राज्यवादी शक्तियों के बीच तीखी प्रतिद्वन्द्विता चल रही थी।

साम्राज्यवादी शक्तियों की दखलन्दाजी के साथ कोरियाई सामंतवाद का संकट उन्नीसवीं सदी में गहराने लगा। कोरियाई बंदरगाहों को साम्राज्यवादी शक्तियों के लिए खोलने को लेकर ये हा-युंग पर दबाव पड़ने लगा था। ये हा-युंग राजा कोजोंङ के स्थान पर शासन कर रहा था। कोजोंङ ये हा-युंग के 1863 में शासन संभालने के समय अल्प वयस्क था। ये हा-युंग ने सामंती व्यवस्था को सुदृढ़ करने के प्रयास किये जो कि उन्नीसवीं सदी में सामंतवाद विरोधी संघर्ष व भावना के कारण कमजोर हो रही थी। कोरिया प्रायद्वीप में 1862 में 20 से अधिक किसान बगावतें हुई थीं।

उन्नीसवीं सदी के प्रारम्भ से ही साम्राज्यवादी ताकतें कोरिया को अपने कब्जे में लेने के लिए प्रयासरत थीं। 1866 में फ्रांस तथा 1871 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने कोरियाई बंदरगाहों पर हमले किये। 1875 में जापान ने अपने युद्धपोत कोरिया भेजे। युद्ध के खतरे को देखते हुए कोरिया जापान के साथ व्यापारिक सन्धि करने के लिए बाध्य हुआ। 1876 में जापान-कोरिया के बीच हुई कांगह्वा (Kanghwa) सन्धि में कोरिया को 'स्वतंत्र' घोषित किया गया। कोजोंङ जिसने 1875 में सत्ता संभाली थी ने कांगह्वा की तर्ज पर ही 1882 में संयुक्त राज्य अमेरिका, 1883 में ग्रेट ब्रिटेन और जर्मनी तथा उसके बाद रूस, फ्रांस तथा अन्य पश्चिम साम्राज्यवादियों को बिना किसी बाधा के व्यापार करने और बसने के अधिकार दिये। साम्राज्यवाद और सामन्तवाद के खिलाफ व्यापक विद्रोह जन्म लेने लगे।

23 जुलाई 1882 को सियोल में एक प्रमुख जापान तथा सरकार विरोधी विद्रोह फूट पड़ा। विद्रोहियों में सैनिक व शहरी नागरिक शामिल थे। विद्रोहियों ने अफसरों के घरों पर हमले किये तथा जापान के राजनयिक मिशन को नष्ट कर डाला। राजा के परिवार तथा बड़े अफसरों को सियोल से भागना पड़ा। कोजोंङ ने चीन के सहयोग से विद्रोह को दबा दिया। मिन परिवार (जो कि कोजोंङ की पत्नी के रिश्तेदार थे) पुनः सत्ता पर काबिज हो गया।

चीन के सामंतवादी शासकों तथा जापानी साम्राज्यवादियों के बीच कोरिया पर प्रभुत्व को लेकर संघर्ष तीखा हो गया। 1885 में जापान और चीन के बीच हुई एक सन्धि के जरिये कोरिया पर दोनों ने एक-दूसरे के अधिकार को मान्यता दे दी तथा अपनी सेनायें कोरिया से हटा लीं। सामंती उत्पीड़न व शोषण, विदेशी हस्तक्षेप तथा अफसरों के भ्रष्टाचार के खिलाफ 1893-94 में कोरिया में किसान विद्रोह भड़क उठा। इसे तोंगहक (Tonghak) विद्रोह के नाम से जाना जाता है। इस विद्रोह को दबाने के लिए पहले चीन और फिर चीनी हस्तक्षेप के खिलाफ जापानी सेनायें कोरिया पहुंच गयीं। चीन और जापान के बीच युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध में जापान विजयी रहा। जापान ने मिन परिवार को सत्ता से क्रमशः हटाकर जापान समर्थित तत्वों को सत्ता में बैठाना प्रारम्भ किया।

उन्नीसवीं सदी के अन्तिम तथा बीसवीं सदी के प्रारम्भिक वर्षों में रूस और जापान के बीच कोरिया को लेकर तीखे संघर्ष शुरू हो गये। 1896 में रूस और जापान के बीच एक सन्धि के जरिये दोनों ने एक-दूसरे के विशेषाधिकारों को मान्यता दे दी। कोरिया की औपचारिक स्वतंत्रता को उसी तरह से मान्यता दी गयी जैसे एक समय चीन और जापान के बीच दी गयी थी।

कोरिया की सोने, लोहे तथा अन्य खनिज खदानों, रेल मार्ग निर्माण आदि गतिविधियों को लेकर जापान, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी ने कोरिया को विभिन्न अपमानजनक संधियों पर हस्ताक्षर करने को बाध्य किया। जापान को सभी साम्राज्यवादी शक्तियों पर वरीयता हासिल थी। 1904 में कोरिया के 70.9% आयात तथा निर्यात के 82.2 % पर जापानी पूंजी का कब्जा था। बैंक से लेकर उद्योग तक जापानी साम्राज्यवादियों के कब्जे में थे।

1904-05 में जापानी तथा रूसी साम्राज्यवादियों के बीच युद्ध भड़क उठा। इस युद्ध में रूसी साम्राज्यवादी हार गये और उन्हें पीछे हटना पड़ा। इस युद्ध में जीत के बाद जापानी साम्राज्यवादियों ने ब्रिटेन और अमेरिका से समझौते करके कोरिया को धीमे-धीमे 1910 में सीधे अपने औपनिवेशिक नियंत्रण में ले लिया।

कोरिया को अपना उपनिवेश बना लेने के बाद जापानी साम्राज्यवादियों ने कोरिया का शोषण और दोहन तीव्र कर दिया। कोरिया जापानी मालों की मण्डी बनने के साथ कच्चे माल का मुख्य स्रोत बन गया। जापानी सम्राट द्वारा नियुक्त सैनिक जनरलों और प्रशासनिक अधिकारियों से युक्त एक सरकार की स्थापना सियोल में कर दी गयी थी। कोरियाई जनता को सभा करने, इकट्ठा होने, भाषण देने, प्रेस

संचालित करने जैसे सभी अधिकारों से वंचित करने के साथ जापानी साम्राज्यवादियों ने कोरिया को जापान में समाहित करने के लिए अपनी शिक्षा व्यवस्था लागू की तथा कोरियाई समाज में जापानी भाषा तथा संस्कृति थोप दी।

औपनिवेशिक सरकार ने एक भू सर्वेक्षण करवा कर जमीन मालिकों को अपनी जमीन के आकार की सूचना देने को बाध्य कर दिया। जापानी साम्राज्यवादियों ने सामंती भू सम्बंधों को नहीं छेड़ा परन्तु बड़ी मात्रा में किसानों की तथा राज्य की जमीन पर कब्जा करके औपनिवेशिक सरकार ने इस कब्जायी गयी जमीन को जापानियों को बेच दिया। 1910 में ऐसे जापानी भू-मालिकों के कब्जे में जहां 87,000 छोंङ बो (1 छोंङ बो बराबर 0.99 हेक्टेयर) जमीन थी वहां यह 1916 आते-आते 200,000 छोंग बो हो गयी। 76 प्रतिशत से अधिक किसान ऐसे थे जिनके पास या तो जमीन नहीं थी या फिर नाम मात्र की थी, जमीन किराये पर लेते थे। किसानों को अपनी फसल का 50 से लेकर 70 प्रतिशत हिस्सा लगान के तौर पर देना होता था। भारी संख्या में किसान जापानी या स्थानीय सूदखोरों के कर्जजाल में फंस गये थे। मजदूर वर्ग के निर्माण की प्रक्रिया जारी थी। जापानी पूंजीपति उद्योग, खान, परिवहन, बैंक आदि सभी क्षेत्रों में छाये हुये थे।

1917 में रूस में हुई समाजवादी क्रांति का व्यापक प्रभाव कोरियाई समाज पर भी पड़ा। कोरिया में 1918 में मजदूर वर्ग की संख्या 126,000 के करीब थी। अक्टूबर क्रांति ने कोरिया के मजदूर वर्ग की वर्गीय मांगों तथा कोरियाई समाज की राष्ट्रीय मुक्ति की आकांक्षा को तीव्र कर दिया। मजदूरों और किसानों के संघर्षों में नया उभार 1919 में आया।

मार्च-अप्रैल 1919 में मजदूरों, किसानों, राष्ट्रीय पूंजीपतियों, विद्यार्थियों के राष्ट्रव्यापी उभार में 20 लाख से अधिक लोगों ने भागीदारी की। इस उभार के दौरान 3200 से अधिक प्रदर्शन और विद्रोह हुए जिसमें 7509 से अधिक लोग मारे गये तथा हजारों की संख्या में लोग जेलों में ठूंसे गये तथा घायल हुए।

इस उभार को कोरिया के इतिहास में प्रथम मार्च आंदोलन (March First Movement) या मेनसेई (Mansei) क्रांति के नाम से जाना जाता है। इस आंदोलन का नेतृत्व राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग ने किया। इन्होंने इसे पहले शांतिवादी रास्ते पर चलाने की कोशिश की, असफल होने तथा आंदोलन के जुझारू और हिंसक तेवर ग्रहण करने पर अपने आपको इस आंदोलन से अलग कर लिया। इस उभार की असफलता का एक प्रमुख कारण यह था कि इसका नेतृत्व सर्वहारा वर्ग के हाथ में नहीं था तथा वह नेतृत्वकारी भूमिका के लिए पर्याप्त ढंग से तैयार नहीं था।

1919 के अगस्त में 'प्रथम मार्च आंदोलन' के उभार के बाद जापानी साम्राज्यवाद ने कुछ संवैधानिक तथा प्रशासनिक सुधार किये तथा राष्ट्रीय पूंजीपतियों को कुछ छूटें दी।

औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ मजदूर वर्ग की संख्या में बढ़ोत्तरी होने लगी। मजदूर वर्ग के संगठनों व संस्थाओं का जन्म होने लगा। 1920 में देशव्यापी पैमाने पर कोरियाई मजदूरों के पहले संगठन 'कोरियाई वर्कर्स कोआपरेटिव' का गठन हुआ। 1921 में इसकी सदस्य संख्या 17,000 थी। इसी दौरान मजदूर अपने को ट्रेड यूनियनों में संगठित करने लगे तथा कई किस्म के जन संगठन भी अस्तित्व में आने लगे। 1920 से 1925 के बीच मजदूरों ने 330 हड़तालें की जिनमें 27,000 मजदूरों ने भाग लिया। रूस की क्रांति के प्रभाव में विद्यार्थियों, बुद्धिजीवियों और मजदूरों के बीच मार्क्सवाद-लेनिनवाद का प्रचार जोर पकड़ रहा था तथा देश में कई स्थानों पर कई किस्म के कम्युनिस्ट ग्रुप जन्म लेने लगे। 1918 में सोवियत यूनियन के सुदूर पूर्व में प्रथम समाजवादी संगठन के रूप में कोरियन सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ। तीन साल बाद यह पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ कोरयो (Koryo- सामंती काल में एक राजवंश के नाम पर कोरिया का नाम) इरकुत्स्क (Irkutsk) नामक स्थान में तथा शंघाई में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ कोरयो' के नाम से विभाजित हो गयी। इसी दौरान 'प्रोलतारियन फेलोशिप सोसाइटी' तथा 'लीग ऑफ मैन ऑफ एडवांस आइडियाज' प्रोलतारी यूनियन में इकट्ठा हो गये। इस यूनियन ने बाद में 1923 में इरकुत्स्क ग्रुप के साथ मिलकर 'सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ न्यू आइडियाज' बनायी। इसने बाद में अपना नाम मंगलवार समाज (Tuesday Society) रख लिया। इसी समय युवाओं और छात्रों के संगठन 'सीयोल यूथ सोसाइटी' (1921) तथा नॉर्थ स्टार सोसाइटी (1923) जैसे कई ग्रुप, अस्तित्व में आये।

देश में मौजूद कम्युनिस्ट ग्रुपों से 17 अप्रैल, 1925 को कम्युनिस्ट पार्टी आफ कोरिया की स्थापना की गई। 1926 में इस पार्टी को अस्थायी तौर पर कम्युनिस्ट इंटरनेशनल में शामिल किया गया। परन्तु इसे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की छठी कांग्रेस (1928) में हैसियत (Status) स्पष्ट न होने के कारण केवल मेहमान का दर्जा हासिल था।

इस पार्टी ने 1925 से 1928 के बीच कई साम्राज्यवाद विरोधी प्रदर्शन तथा मजदूरों की हड़तालें आयोजित कीं। जून 1926 में इसके द्वारा आयोजित प्रदर्शन जो कि जन चरित्र लिए हुए था, में दो लाख से अधिक लोगों ने भागीदारी की। कम्युनिस्ट पार्टी के सहयोग व नेतृत्व से 1925 से 1928 के बीच 349 हड़तालें आयोजित हुईं। इसी दौरान (1925 से 1928) किसानों ने लगान के खिलाफ कई हड़तालें व प्रदर्शन आयोजित किये। 1926 से 1928 के बीच इनकी संख्या 2063 तक पहुंच गयी थी। कई प्रदर्शनों ने खुले विद्रोह का रूप भी अख्तियार किया। मजदूरों और किसानों के आंदोलनों का प्रभाव विद्यार्थियों पर भी पड़ा। 1926 में 55 तथा 1928 में 83 विद्यार्थियों और युवाओं के आंदोलन हुए। साम्राज्यवाद विरोधी संघर्षों के उभार के दौरान कम्युनिस्ट पार्टी ने 1927 में एक व्यापक देशभक्त जनमोर्चा 'सिनगेन होई' (Singan hoe) या नव कोरियाई समाज (New Korea Society) का गठन किया। यह मोर्चा 1931 तक कायम रहा।

परन्तु यह पार्टी अत्यन्त अल्पजीवी साबित हुई। संकीर्णतावादी तथा दक्षिणपंथी भटकावों के साथ जापानी साम्राज्यवाद के दमन व घृणित चालों व बढ़ती गुटबाजी से पार्टी 1928 में विघटित हो गयी। पार्टी के विघटन के बावजूद कई कम्युनिस्ट ग्रुप देश के प्रमुख औद्योगिक केन्द्रों व शहरों में गुप्त ढंग से सक्रिय रहे।

1929-33 के विश्व व्यापी आर्थिक संकट का व्यापक प्रभाव कोरिया पर भी पड़ा। जापानी साम्राज्यवादी शोषण-उत्पीड़न-दमन को तीव्र करते जा रहे थे। 1931 में जापान ने मंचूरिया पर हमला बोल दिया। कोरिया जापान की युद्ध मशीन के लिए मनुष्य और लोहे का खुला स्रोत बन गया। पूरे दूसरे विश्व युद्ध के दौरान कोरिया जापान के हथियार उद्योग के लिए आधार बन गया था। जापान खनिज पदार्थों के मामले में कोरिया के मुकाबले प्राकृतिक रूप से विपन्न है। कोरिया में कोयले, लोहे तथा अन्य किस्म के खनिज पदार्थों के विशाल भण्डार हैं।

जापानी साम्राज्यवादियों तथा सामंतवाद के खिलाफ कोरिया की जनता के संघर्षों का सिलसिला जारी था। पूरे कोरिया में जापानी साम्राज्यवाद विरोधी संघर्षों की छात्रों ने 1929 में झड़ी लगा दी थी। 1929 में क्वांगजू में छात्रों ने राजनीतिक स्वतंत्रता तथा शिक्षातंत्र को बदलने के व्यापक प्रदर्शन किये। औपनिवेशिक सत्ता ने छात्रों के आंदोलन को क्रूरतापूर्वक दबा दिया। 1930, 1931, 1932 के वर्ष किसानों और मजदूरों के व्यापक असंतोष के वर्ष रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में इस दौरान मजदूरों ने हड़तालें की जिनमें भागीदारी करने वाले मजदूरों की संख्या साठ हजार से भी अधिक थी। यही हाल समय-समय पर फूट पड़ने वाले किसान संघर्षों का था। मजदूरों के संघर्षों में 1929 की खनिकों द्वारा वोनसान शहर में की गई हड़ताल तथा किसानों के विद्रोहों में 1930 में तानचोन जिले में किया गया सशस्त्र विद्रोह प्रमुख थे।

किसानों, मजदूरों, विद्यार्थियों के आंदोलन के प्रभाव में मंचूरिया में जापान-विरोधी देशभक्त सशस्त्र संघर्ष पैदा होने लगा था। मंचूरिया उत्तरी-पूर्वी चीन में स्थित है। यहां उस वक्त दस लाख से भी अधिक कोरियाई रह रहे थे। किम इल-सुंग के नेतृत्व में तथा कम्युनिस्टों के दिशा निर्देशन में सशस्त्र संगठन के रूप में कोरियन पीपुल्स रिवोल्यूशनरी आर्मी (KPRA) 1934 में अस्तित्व में आई।

कुछ बातें किम इल-सुंग के बारे में।

किम इल-सुंग का जन्म 15 अप्रैल 1912 को प्योंगयांग शहर के निकट मांग युंग देई (Mangyungdai) जिले में एक देशभक्त किसान परिवार में हुआ। छोटी उम्र में ही किम इल सुंग साम्राज्यवाद विरोधी संघर्षों में सक्रिय हो गये थे। 1926 में उन्होंने 'डाउन विद इम्पीरियलिज्म यूनियन' (DIU) गठित की तथा एक वर्ष बाद इसे 'एण्टी इम्पीरियलिस्ट यूथ लीग (AIYL) में पुनर्संगठित किया। इसके साथ ही 'यंग कम्युनिस्ट लीग' (YCL) का भी गठन किया। 1928 में किरीन-होयरयंङ (Kirin-Hoeryong) रेलवे मार्ग निर्माण के खिलाफ छात्रों के एक संघर्ष का नेतृत्व किया जिसके फलस्वरूप किम इल-सुंग को सात माह की जेल हुई।

1930 में YCL तथा AIYL के सदस्यों को लेकर किम इल-सुंग ने कोरियन रिवोल्यूशनरी आर्मी की पहली यूनिट का गठन किया। जापानी प्रभुत्व में पड़ने वाले इलाके से इस आर्मी के हेड क्वार्टर को पूर्वी मंचूरिया में स्थानान्तरित कर दिया गया।

1931 में जापान ने मंचूरिया पर हमला बोल दिया। इसने किम इल-सुंग को जापान के खिलाफ गुरिल्ला लड़ाई के लिए बाध्य कर दिया। मंचूरिया के आंटू (Antu) में 'एण्टी जैपनीज पीपुल्स गुरिल्ला आर्मी (AJPGA) का 25 अप्रैल 1932 को गठन किया गया। मंचूरिया में बसे कोरियाई लोगों की संख्या कई लाख थी। यहां कम्युनिस्टों का काम था। किम इल-सुंग को जुझारू संगठन बनाने के कार्य में सोवियत संघ तथा चीन के कम्युनिस्टों का सहयोग हासिल था। वे हथियार बंद संगठन बनाने में मदद कर रहे थे। किम इल-सुंग ने इसकी स्थापना के समय लक्ष्य को स्पष्ट करते हुए कहा,

> " पीपुल्स गुरिल्ला आर्मी का लक्ष्य और मिशन कोरिया में जापानी साम्राज्यवाद के औपनिवेशिक शासन को उखाड़ फेंकना व राष्ट्रीय आजादी तथा कोरियाई जनता की सामाजिक मुक्ति हासिल करना है ... AJPGA की स्थापना एक ऐसी अवस्था को प्रारम्भ करेगी जिसमें जापान विरोधी संयुक्त मोर्चा की लाइन तथा एक मार्क्सवादी-लेनिनवादी पार्टी की नीति लागू हो सके।"
>
> (N. Steinmayr द्वारा जनवरी 1999 में लिखे गये पैम्फलेट Long live Korean Re unification! Down with Korean Revisionism! में Kim IL Sung,Works, Vol-1 Pyongyang 1980, पृष्ठ 47 से उद्धृत)

मार्च 1934 में AJPGA को पीपुल्स रिवोल्युशनरी आर्मी (KPRA) में पुनर्संगठित कर दिया गया। फरवरी 1936 में KPRA के सैनिक व राजनीतिक नेताओं की एक कान्फ्रेंस लिओंगक्यू (LiaongKou) शहर में हुई। कोमिंटर्न की सातवीं कांग्रेस के दिशा निर्देशानुसार एक ऐसी नीति तय करनी थी जिसके हिसाब से सभी देशभक्त ताकतों को एकजुट करके एक जापान विरोधी राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा गठित हो सके। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते 'चोगुक क्वांगबोकहोई' अर्थात् 'सोसाइटी फार द रिवाईवल ऑफ फादरलैण्ड' (Choguk Kwangbokhoe- Society for the Revival of the Father Land) की स्थापना की गई। इस सोसाइटी का प्रोग्राम : जापानी शासन को समाप्त करना, एक स्वतंत्र जनवादी कोरियाई राज्य की स्थापना करना, जनता की सरकार बनाना, जापानी साम्राज्यवादी और उनके साथ रहे सहअपराधी कोरियाइयों से सम्बन्धित उद्योग, बैंक, रेलमार्ग और जमीन को जब्त करना तथा राजनीतिक सामाजिक-आर्थिक व सांस्कृतिक परिवर्तन करना, था।

इस सोसाइटी को अपने प्रोग्राम को लागू करने के लिए सभी कानूनी-गैर कानूनी रास्ते अख्तियार करने थे तथा व्यापक स्तर पर उद्वेलनात्मक तथा प्रचारात्मक कार्यवाहियां अंजाम देनी थीं।

अपनी स्थापना के बाद इस सोसाइटी ने सैनिक कार्यवाहियां प्रारम्भ कर दीं तथा जून 1937 में पो चोंग बो शहर में जापानी सैनिक टुकड़ी पर हमला बोल दिया। इस तरह से जापान विरोधी सशस्त्र संघर्ष में कोरियाई जनता की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी प्रारम्भ हुई। जिसने बाद में जापानी साम्राज्यवाद की दूसरे विश्व युद्ध में पराजय में योगदान दिया।

1938 में चीन-जापान युद्ध प्रारम्भ हुआ, जापानी साम्राज्यवाद के खिलाफ पूरे कोरिया में जनता लामबंद हो गयी। जापानी साम्राज्यवादियों ने भारी संख्या में कोरियाई स्त्री-पुरुषों को अपनी सेना में भर्ती करके युद्ध में झोंका। KPRA ने पूरे कोरिया में जापानी साम्राज्यवादियों के खिलाफ माहौल तैयार किया।

9 मई 1945 को नाजी जर्मनी ने सोवियत सेनाओं के सामने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया। 9 अगस्त 1945 को सोवियत सेनाओं ने जापानी साम्राज्यवादियों के खिलाफ हमला बोल दिया। जापानी सैनिक साम्राज्यवादियों की क्वांङतुंङ सेना को सोवियत सेनाओं ने नष्ट कर डाला और कोरिया में जापानी साम्राज्यवादियों की भूमिका को समाप्त कर दिया। उधर KPRA ने देश के कई शहरों को जापानी साम्राज्यवादियों से मुक्त करा दिया। 15 अगस्त 1945 को जापानी सेनाएं बिना शर्त आत्म समर्पण को बाध्य हुयीं।

याल्टा (फरवरी 1945) तथा पोटस्डम (जुलाई-अगस्त 1945) में मुख्यतः सोवियत संघ तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच हुए समझौतों के अनुसार कोरिया के उत्तरी हिस्से में जापानी सेनाओं को सोवियत सेनाओं तथा दक्षिणी हिस्से में जापानी सेनाओं को अमेरिका के समक्ष आत्म समर्पण करना था। सितम्बर 1945 में इस काम के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की सेनाएं दक्षिणी कोरिया पहुंचीं। 38^0 अक्षांश के इर्द-गिर्द कोरिया प्रायद्वीप को विभाजित करने वाली रेखा अमेरिकी साम्राज्यवादियों ने अपने घृणित मंसूबों को पूरा करने के लिए खींच डाली। सोवियत संघ तथा चीन के खिलाफ अमेरिका अपनी एक चौकी सुदूर पूर्व में स्थापित करना चाहता था। तात्कालीन वर्गीय शक्ति संतुलन इस तरह से कायम हुआ कि अमेरिका अपने मंसूबों में कामयाब हो गया।

कोरिया की एकता कोरियाई जनता की एक ऐसी आकांक्षा रही है जो आज तक अधूरी है। तब भी सबसे बड़ी बाधा अमेरिकी साम्राज्यवाद था, आज भी वही है।

जापानी साम्राज्यवादियों की निर्णायक शिकस्त के बाद यह आवश्यक था कि सामन्ती तत्वों का सफाया किया जाए और जनता की जनवादी आकांक्षाओं की पूर्ति की जाए। अर्थात कोरिया की जनता को जनवादी क्रांति पूरी करने की जरूरत थी। इस काम को मजदूर वर्ग के नेतृत्व में और उसकी पार्टी के जरिये ही मुकम्मिल ढंग से किया जा सकता था।

कुछ मामलों में कोरियाई क्रांति का इतिहास अनूठा है। उत्तरी कोरिया में सत्ता पर कब्जा पहले हुआ और कम्युनिस्ट पार्टी का गठन बाद में। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि कोरिया में कम्युनिस्ट ग्रुप और कम्युनिस्ट प्रभाव मौजूद नहीं था। हम देख आये हैं कि कोरिया की साम्राज्यवाद से मुक्ति में सोवियत सेनाओं के इतर कोरिया के मजदूरों, किसानों, युवाओं, विद्यार्थियों, बुद्धिजीवियों, राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग के साथ कम्युनिस्ट तत्वों की बड़ी भूमिका थी। KPRA का एक लक्ष्य देश में मार्क्सवादी-लेनिनवादी पार्टी की स्थापना करना था। किम इल-सुंग साम्राज्वाद विरोधी संघर्ष के नेता बन कर उभरे थे।

किम इल-सुंग के नेतृत्व में कम्युनिस्ट पार्टी के गठन के प्रयास तुरन्त ही शुरू हो गये। 10-13 अक्टूबर 1945 को किम इल-सुंग ने उत्तरी कोरिया के पांच प्रांतों के जिम्मेदार पार्टी नेताओं की कांफ्रेंस आहूत की ताकि पार्टी की स्थापना की जा सके। इस कांफ्रेंस में 70 प्रतिनिधि उपस्थित थे। इस कांफ्रेंस ने पार्टी की राजनैतिक व सांगठनिक लाइन स्वीकार की।

पार्टी की स्थापना के समय दिया गया किम इल-सुंग का बयान भविष्य तथा पार्टी की स्थापना में पेश हुयी चुनौती की दृष्टि से महत्वपूर्ण है,

> "हमने मार्क्सवाद-लेनिनवाद के पार्टी निर्माण के सिद्धान्तों के एकदम अनुरूप पार्टी को पुनर्निर्मित किया है, इसके नाभिक में ऐसे कम्युनिस्ट हैं जो कि क्रांतिकारी संघर्ष में तपे हैं, ...
>
> "हमारी पार्टी का जन्म मुक्ति के बाद उत्पन्न हुई उन अत्यन्त जटिल और अव्यवस्थित परिस्थितियों में हुआ है जबकि वर्ग शत्रु विनाशक दांव चल रहे थे और सभी तरह के अवसरवाद के साथ गुटबाजी और संकीर्णता (Provincialism) छायी हुयी थी।....
>
> (किम इल-सुंग का उद्धरण,
>
> Kim IL Sung Biography (II) by BAIK BONG, पृष्ठ- 47, Published By MIRAISHA TOKYO, JAPAN 1970, अनुवाद हमारा)

पार्टी की स्थापना के बाद कई तरह के जनवादी संगठन स्थापित किये गये। (18 नवम्बर, 1945) नार्थ कोरियन डेमोक्रेटिक वूमेंन्स यूनियन, (30 नवम्बर, 1945) नार्थ कोरियन जनरल फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन्स, (17 जनवरी, 1946) नार्थ कोरियन डेमोक्रेटिक यूथ लीग तथा (31 जनवरी, 1946) नॉर्थ कोरियन पीजेंट्स यूनियन प्रमुख थे।

फरवरी, 1946 में पूरे देश के मजदूरों, किसानों तथा देशभक्त हिस्सों के स्थानीय स्तर के प्रतिनिधियों के आधार पर प्रोविजनल पीपुल्स कमेटी की कांफ्रेंस हुई। इस कांफ्रेंस में जनवादी पार्टियों, सामाजिक संगठनों, प्रशासनिक इकाइयों तथा पीपुल्स कमेटियों का प्रतिनिधित्व था। इस कमेटी ने किम इल-सुंग को सर्वसम्मति से चेयरमैन चुना। इस कमेटी द्वारा देश में जनवादी क्रांति को आगे बढ़ाया जाना था तथा जनता की तानाशाही स्थापित करनी थी।

किम इल-सुंग ने 23 मार्च 1946 को कम्युनिस्ट पार्टी के प्रोग्राम के आधार पर नॉर्थ कोरियन प्रोविजनल पीपुल्स कमेटी के 20 सूत्रीय घोषणा पत्र को स्वीकार किया। जिसके आधार पर एक के बाद एक जनवादी कदम उठाये गये जो कि अपने चरित्र में सामन्तवाद व साम्राज्यवाद विरोधी थे। मार्च 1946 में किये गये भूमि सुधार के जरिये जमींदारों के भू अधिकारों तथा किराये की व्यवस्था (Rent System) को समाप्त कर दिया गया। भूसम्पत्तिधारियों की दस लाख छौंङ बो से अधिक जमीन 720,000 किसान परिवारों के बीच बांट दी गई जो कि पहले या तो भूमिहीन थे या फिर नाममात्र की जमीन रखते थे। अगस्त 1946 में उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया जिसका नतीजा यह निकला कि राज्य का उत्पादन के साधनों के अस्सी फीसदी भाग पर कब्जा हो गया। जून 1946 में श्रम कानून तथा जुलाई 1946 में स्त्री-पुरूष बराबरी कानून बनाया गया। (20 सूत्री घोषणा पत्र को लेख के अंत में परिशिष्ट के तौर पर दे दिया गया है।)

अपनी स्थापना के दस महीने के भीतर कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्यता 270,000 तक पहुंच गयी तथा देश भर में पार्टी के 12,000 सैल काम कर रहे थे।

कम्युनिस्ट पार्टी को जन आधारित पार्टी बनाने के लिए किम इल-सुंग ने कम्युनिस्ट पार्टी और न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के एकीकरण से उत्तरी कोरिया की मजदूर पार्टी बनाने का प्रस्ताव रखा। 28-30 अगस्त, 1946 को उत्तरी कोरिया की मजदूर पार्टी (North Korean Workers Party) की स्थापना कांग्रेस हुई। इस कांग्रेस में 801 प्रतिनिधियों ने भाग लिया जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के 276,000 तथा न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के 90,000 सदस्यों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। कम्युनिस्ट पार्टी और न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी की एकता का आधार किम इल-सुंग के अनुसार न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी का प्रोग्राम तथा कम्युनिस्ट पार्टी के तात्कालिक कार्यभारों का एक होना था।

उत्तरी कोरिया की कम्युनिस्ट पार्टी में कुछ व्यक्तियों द्वारा किम इल-सुंग के इस कदम की यह कह कर आलोचना की गई कि यह पार्टी को निम्न बुर्जुआ पार्टी में तब्दील करना है। न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी का मुख्य आधार किसानों के बीच था।

किम इल-सुंग ने दो पार्टियों के विलय के महत्व के बारे में यह कहा,

> "हमारी पार्टी तथा न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी का विलय करके मजदूर पार्टी बनाना, मेहनतकश जनता की एकीकृत राजनीतिक पार्टी बनाना हमारी क्रांतिकारी शक्तियों को सुदृढ़ करने में एक युगान्तरकारी घटना है।
>
> "एकीकरण के फलस्वरूप हमारी पार्टी जन राजनीतिक पार्टी बन जायेगी जो कि अपने भीतर न केवल मजदूर वर्ग के अगुवा तत्वों बल्कि मेहनतकश किसानों तथा मेहनतकश जनता के बीच काम करने वाले बुद्धिजीवियों को भी समेट लेगी।
>
> "कम्युनिस्ट पार्टी और न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी का विलय इस बात की सम्भावना को बढ़ायेगा कि पार्टी की शक्ति बढ़ सके तथा क्रांतिकारी कतारों का विस्तार हो सके ... साथ ही यह मेहनतकश जनता की वर्तमान दो पार्टियों के होने से क्रांतिकारी शक्तियों में होने वाले विभाजन से रक्षा करेगा..." (पृष्ठ 147, वही)

किम इल-सुंग ने अन्य जगह इस बात को कहा था कि यह पार्टी मार्क्सवादी-लेनिनवादी सिद्धान्तों के आधार पर चलेगी। मोटे तौर पर किम इल-सुंग की अवस्थिति को ठीक मानते हुए हम इस सवाल को भविष्य में बनने वाले किसी अन्तर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट केन्द्र पर छोड़ते हैं कि किम इल-सुंग का यह कदम कितना सही और गलत था, या किम इल-सुंग के राष्ट्रवादी भटकावों या भविष्य में एक समय बाद पार्टी के मार्क्सवाद-लेनिनवाद को तिलांजलि देने में कितनी भूमिका थी। एक अन्य चीज जो हमारे निर्णय में बाधा पैदा करती है वह यह है कि 1946 में न केवल अन्तर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट आंदोलन बहुत सशक्त था बल्कि उस वक्त स्तालिन और माओ जैसे शिक्षक भी मौजूद थे। हमारी जानकारी में किम इल-सुंग या कोरियाई कम्युनिस्टों के इस कदम पर स्तालिन या माओ की कोई टिप्पणी या प्रतिक्रिया नहीं है। इसलिए मोटे तौर पर किम इल-सुंग की अवस्थिति को ठीक मानते हुए इस सवाल को हम भविष्य के लिए छोड़ते हैं।

इस विलय के बाद पार्टी-उत्तरी कोरिया की मजदूर पार्टी (WPNK) जिसका नाम बाद में कोरिया की मजदूर पार्टी कर दिया गया था- की सदस्यता एक वर्ष के भीतर 680,000 हो गयी। 1946 में उत्तरी कोरिया की मजदूर पार्टी ने दो अन्य पार्टियों [डेमोक्रेटिक पार्टी तथा चोगू (Chogu) पार्टी] तथा अन्य जनवादी संगठनों के साथ मिलकर 'डेमोक्रेटिक नेशनल यूनाइटेड फ्रंट ऑफ नॉर्थ कोरिया (DNUFNK) बनाया।

46-47 में देशभर में पीपुल्स कमेटी के चुनाव हुये जिसके आधार पर 17 फरवरी 1947 को पीपुल्स असेम्बली बनायी गयी। इस पीपुल्स असेम्बली में 237 सदस्य थे। विभिन्न पार्टियों की स्थिति असेम्बली में प्रतिशत के अनुसार, WPNK-36%; डेमोक्रेटिक पार्टी-13%; चोगू पार्टी-13% तथा शेष-38% असम्बन्धित थे। सामाजिक वर्गों की दृष्टि से इस असेम्बली की स्थिति इस प्रकार थी, मजदूर-22%; किसान-26%; कार्यालय कर्मचारी-24%; बुद्धिजीवी-15%; उद्योगपति (Enterprisers) -3%; व्यापारी-4%; दस्तकार-2% तथा धार्मिक व्यक्ति-4%।

जापानी साम्राज्यवादियों ने अपने आत्मसमर्पण के पहले कोरिया के उद्योगों, खानों, पावर स्टेशनों, सड़कों-पुलों, रेलमार्गों को या तो पूर्णतः नष्ट कर दिया था या भारी नुकसान पहुंचाया था। 19 हाइड्रो-इलेक्ट्रिक पावर प्लांट काम लायक नहीं थे, 64 खानों में पूर्ण रूप से तथा 178 में आंशिक रूप से पानी भरा हुआ था, प्योंगयांग की एअरक्राफ्ट फैक्ट्री, 6 बड़े उद्योग नष्ट कर दिये गये थे। यही हाल कमोबेश अन्य क्षेत्रों का था।

कृषि सुधारों के साथ उद्योग तथा अवरचनागत क्षेत्र का तेजी से विकास किया गया। 1946 की तुलना में औद्योगिक उत्पाद में 1947 में 53%, 1948 में 117.9% तथा 1949 में 233.3% की वृद्धि दर्ज की गई।

पीपुल्स असेम्बली द्वारा पारित किये गये संविधान के आधार पर 9 सितम्बर 1948 को उत्तरी कोरिया को जनवादी जन गणतंत्र कोरिया (Peoples Democratic Republic Of Korea) के रूप में मान्यता दे दी गयी।

III
कोरियाई विभाजन और अमेरिकी साम्राज्यवाद

1945 में दक्षिण कोरिया जापानी साम्राज्यवादियों से मुक्त होने के बाद अमेरिकी साम्राज्यवादियों का नवउपनिवेश बन गया था। दक्षिण कोरिया में जमींदारों और बड़े पूंजीपतियों की सत्ता कायम हुई थी। इस सत्ता का नेतृत्व अमेरिका के दलालों के हाथों में था। 1948 से लेकर 1960 तक दक्षिण कोरिया का शासन तानाशाह सिंग मेन री के हाथों में था। यह सिंग मेन री वही था जिसने अप्रैल 1919 में कुछ अन्य बुर्जुआ तत्वों के साथ मिलकर शंघाई में अस्थायी सरकार बनाई थी। सिंग मेन री के शासनकाल में अमेरिकी साम्राज्यवादियों को विशेषाधिकार हासिल थे। वस्तुतः वह अमेरिकी साम्राज्यवादियों की कठपुतली था। 1960 में छात्रों,मजदूरों किसानों तथा जनता के अन्य हिस्सों के विद्रोह और प्रदर्शन के फलस्वरूप उसके लम्बे शासन-काल का अंत हुआ।

1945 में कोरिया के विभाजन को कोरिया प्रायद्वीप की जनता ने नहीं स्वीकारा था। दक्षिण कोरिया की जनता उत्तरी कोरिया में हो रही साम्राज्यवाद-सामन्तवाद विरोधी जनवादी क्रांति से अत्यधिक प्रभावित थी और वह शीघ्र से शीघ्र एकीकरण चाहती थी। उत्तरी कोरिया की मेहनतकश जनता भी पूरे देश की एकता चाहती थी। '45 से '49 के बीच एकीकरण के लिए तमाम किस्म के शांतिपूर्ण प्रयास किये गये। अमेरिकी साम्राज्यवादी और उनके दक्षिण कोरियाई पिट्ठू हर शांतिपूर्ण प्रयास में अड़ंगे लगाते रहे।

1949 से ही 38° अक्षांश वाली सीमा-रेखा पर उत्तरी कोरिया की पीपुल्स आर्मी और दक्षिण कोरिया की सेनाओं के बीच झड़पें शुरू हो गयी थी। 4 मई, 1949 को दक्षिण कोरिया की सेनाओं ने काईसोंङ की ओर हमला बोल दिया। इस हमले में उत्तरी कोरिया के 4000 सैनिक, दक्षिण कोरिया के 22 सैनिक तथा सौ से अधिक नागरिक मारे गये।

सिंग मेन री की सरकार अमेरिकी साम्राज्यवादियों की सरपरस्ती तथा उनकी सेना के सीधे सहयोग से सैनिक ढंग से उत्तरी कोरिया पर कब्जा करके देश के एकीकरण की फिराक में थी। अमेरिकी साम्राज्यवादी पूरे कोरिया प्रायद्वीप को अपने कब्जे में लेना चाहते थे। अपना नवउपनिवेश बनाना चाहते थे। इस दौरान दक्षिण कोरिया की जनता में री शासन के खिलाफ गुस्सा भड़क रहा था। री जनता के आंदोलनों को क्रूरतापूर्वक कुचल रहा था। कम्युनिस्टों के दमन के नाम पर आम नागरिकों का भी कत्लेआम कर रहा था। 1950 में हजारों की संख्या में लोगों की हत्याएं की गयी तथा सैकड़ों घरों को नष्ट कर दिया गया।

25 जून 1950 को दक्षिण कोरिया की सेनाओं ने उत्तरी कोरिया पर 38° अक्षांश सीमा रेखा पर कई ओर से हमला बोल दिया। इस तरह से तीन वर्षीय (1950-1953) युद्ध कोरिया की जनता पर थोप दिया गया।

अमेरिका ने अपनी सेनाएं संयुक्त राष्ट्र संघ के बैनर तले उतारी थीं। यह हालांकि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्तावों के खिलाफ था। सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ के बायकॉट को देखते हुए अमेरिका द्वारा इस बैनर का इस्तेमाल गलत था। सोवियत संघ ने लोक गणराज्य चीन को सुरक्षा परिषद में शामिल न करने के चलते उसका बायकॉट किया हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ के बैनर के बावजूद यह सेना मुख्यतः अमेरिकी सेना थी।

युद्ध के प्रारम्भिक महीनों में (जून से सितम्बर 1950) उत्तरी कोरिया की पीपुल्स आर्मी ने 'संयुक्त राष्ट्र की सेना' को धकेलना शुरू किया और एक तरह से कोरिया प्रायद्वीप के 90 फीसदी से अधिक भू-भाग पर कब्जा कर लिया। 'संयुक्त राष्ट्र की सेना' पूसान नामक क्षेत्र तक सिमट कर रह गयी।

नवम्बर के महीने से अमेरिकी साम्राज्यवादियों की सेना ने तेजी से आगे बढ़ना शुरू किया। अमेरिका ने भारी संख्या में सैनिक और हथियार इस युद्ध में झोंक दिये। अमेरिका की वायुसेना ने उत्तरी कोरिया के कल-कारखानों, पुलों, सड़कों सभी जगहों पर भारी बमबारी शुरू कर दी। अमेरिका ने नापाम बमों से लेकर जैविक हथियारों का इस्तेमाल किया। उत्तरी कोरिया के समर्थन में चीन ने स्वयं सेवकों की सेना संगठित की और उसे युद्ध के मोर्चे पर भेजा। कोरिया और चीन की जनता कंधे से कंधा मिलाकर साम्राज्यवादी आक्रमण का सामना करने के लिए उठ खड़ी हुई। सोवियत संघ तथा अन्य समाजवादी देशों की सरकारों और जनता ने कोरिया की जनता को बड़े पैमाने पर सहयोग और समर्थन दिया।

27 जुलाई 1953 को 38° अक्षांश रेखा को सीमा मानते हुए अमेरिकी साम्राज्यवादी और उसके पिछलग्गू युद्ध विराम करने के लिए बाध्य हुये।

इस युद्ध में भारी संख्या में आम नागरिक मारे गये। कुल मारे गये लोगों की संख्या चालीस लाख से अधिक आंकी गयी। 1954 में अमेरिका ने स्वीकारा कि इस युद्ध में उसके 33,269 आदमी या तो सीधे युद्ध में या गम्भीर घावों के कारण मारे गये, 103,284 घायल हुये तथा 4,753 गुम हो गये जिन्हें बाद में मृत मान लिया गया। अमेरिकी अनुमानों के अनुसार घायल और मारे गये चीनियों की संख्या 9 लाख और कोरियाइयों की संख्या पांच लाख बीस हजार थी।

उत्तरी कोरिया को युद्ध के कारण भारी नुकसान उठाना पड़ा था। अमेरिकी साम्राज्यवादियों ने उत्तरी कोरिया में उत्पादन के साधनों को भारी पैमाने पर नष्ट किया था। इस सबके बावजूद इस युद्ध से अमेरिकी साम्राज्यवादी मनोवांछित चीज नहीं पा सके थे और उन्हें मुंह की खानी पड़ी थी।

12 सितम्बर 1953 को माओ ने इस सम्बंध मे लिखा था,

"अमरीकी आक्रमण का प्रतिरोध करने और कोरिया की सहायता करने के युद्ध में तीन वर्ष बाद हमने महान विजय प्राप्त कर ली है।.....

"इस विजय का श्रेय किसे दिया जाना चाहिए? सभी सदस्य महानुभावों ने इसका श्रेय सही नेतृत्व को दिया है। नेतृत्व इसका एक कारण है; बिना सही नेतृत्व के कोई भी काम सफल नहीं हो सकता। लेकिन हमें विजय मुख्य रूप से इसलिए प्राप्त हुई क्योंकि हमारा युद्ध एक लोकयुद्ध था, इसका समर्थन समूची जनता करती थी तथा इसमें चीन और कोरिया की जनता कंधे से कंधा मिलाकर लड़ी।

"हमने अमरीकी साम्राज्यवाद से लोहा लिया, एक ऐसे दुश्मन से लोहा लिया जिसके हथियार हमसे कई गुना बेहतर हैं, फिर भी हमने उस पर विजय प्राप्त की और उसे युद्ध-विराम के लिए बाध्य कर दिया। युद्ध-विराम क्यों सम्भव हो सका?

"पहले, सैनिक दृष्टि से अमरीकी आक्रमणकारी प्रतिकूल स्थिति में और पिटने की स्थिति में थे।.....

"दूसरे, राजनीतिक दृष्टि से हमारा दुश्मन बहुत से ऐसे अंदरूनी अंतर्विरोधों का सामना कर रहा था जिन्हें हल नहीं किया जा सकता था, तथा समूची दुनिया की जनता शान्ति की मांग कर रही थी।

"तीसरे, आर्थिक दृष्टि से दुश्मन ने कोरिया पर आक्रमण करने के युद्ध में बहुत सा धन खर्च किया था तथा उसके बजट में आमदनी और खर्च के बीच असन्तुलन पैदा हो गया था।

"इन्हीं सब कारणों ने मिलकर दुश्मन को समझौते के लिए बाध्य कर दिया।"

(माओ, 'अमरीकी आक्रमण का प्रतिरोध करने और कोरिया की सहायता करने के युद्ध में हमारी महान विजय तथा हमारे आगामी कार्य; 12 सितम्बर 1953, माओ त्से तुंङ की संकलित रचनायें, ग्रंथ-5, पृष्ठ- 97-98, प्रोग्रेसिव पब्लिकेशन्स, दिल्ली)

1953 में हुआ युद्ध विराम आज तक जारी है। अमेरिकी साम्राज्यवादियों के कारण उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच कोई स्थायी शान्ति सन्धि तक नहीं हो सकी। उत्तरी कोरिया की सीमाओं पर तब से अमेरिकी फौजें तैनात हैं। एक समय तक तो खुले तौर पर अमेरिका ने नाभिकीय हथियार भी तैनात किये हुए थे। उत्तरी कोरिया की सैनिक घेरेबंदी आज भी जारी है। शक्तिशाली दक्षिण कोरियाई सेना के बावजूद आज भी 37,000 अमेरिकी सैनिक और भारी पैमाने पर जनसंहारक हथियार दक्षिण कोरिया में मौजूद हैं।

अमरीकी साम्राज्यवादी कोरिया प्रायद्वीप में किसी स्थायी सन्धि और आगे बढ़कर कहा जाय तो कोरियाई एकता के घोर विरोधी हैं। अमेरिकी साम्राज्यवादियों के मंसूबे कितने साफ रहे हैं यह उसका 1945 से अब तक का इतिहास एकदम साफ तौर पर दर्शाता है। जापानी साम्राज्यवादियों की निर्णायक शिकस्त के बाद तात्कालीन सोवियत संघ ने अपनी फौजें 1948 में ही हटा ली थीं। उसी तरह 1950-1953 के युद्ध की समाप्ति के बाद चीन की स्वयंसेवक सेना ने भी उत्तरी कोरिया को छोड़ दिया था परन्तु अमेरिका की फौजें दक्षिण कोरिया में तब भी बनी हुई हैं जबकि दक्षिण कोरिया के पास आधुनिक हथियारों से लैस एक सेना है।

दक्षिण कोरिया और अमेरिका की सेनाओं के द्वारा प्रतिवर्ष 'टीम स्प्रिट' (Team Spirit) नाम से वार्षिक संयुक्त युद्धाभ्यास 1969 से हो रहे हैं। इन युद्धाभ्यासों के समय अमेरिका और दक्षिण कोरिया की सेनाएं उत्तरी कोरिया पर सामरिक हमले का युद्धाभ्यास करतीं हैं और उत्तरी कोरिया पर सैनिक दबाव बनाने के प्रयास किये जाते हैं। अभ्यास कितने बड़े पैमाने पर होते हैं इसका अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि इसमें शामिल सैनिकों की संख्या 2 लाख तक होती है। साथ ही यह भी एक तथ्य है कि 1953 से ही अमेरिका लगातार सीमित नाभिकीय युद्ध की धमकी देता रहा है। सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका ने खुले तौर पर नाभिकीय हथियार दक्षिण कोरिया से हटाये थे जिसमें एक बड़ा योगदान दक्षिण कोरिया की जनता का था। दक्षिण कोरिया की जनता लगातार ही अमेरिकी सेनाओं तथा हथियारों की तैनाती का विरोध करती रही।

युद्ध विराम का कभी भी स्थायी शान्ति समझौते में तब्दील न होना, तमाम किस्म के आर्थिक व तकनीकी प्रतिबंध, अमरीकी सेनाओं तथा नाभिकीय हथियारों की दक्षिण कोरिया तथा जापान में उपस्थिति, दक्षिण कोरिया के शासकों के लगातार युद्ध छेड़ने के मंसूबों (जो कम से कम 1993 तक जारी थे। 1993 से स्थायी तौर से गैर-सैनिक और चुनाव लड़कर, जीतकर नागरिक सरकारें दक्षिण कोरिया में अस्तित्व में आयी हैं। नग्न सैनिक तानाशाहियों के दौर समाप्त हुये हैं।) के बीच उत्तरी कोरिया को 1953 और एक तरह से 1945 से ही युद्ध की मानसिकता में जीना पड़ रहा है। उत्तरी कोरिया को हमेशा ही साम्राज्यवादी अमेरिका द्वारा किसी भी समय युद्ध छेड़ने की सम्भावना के बीच रहना पड़ा है।

IV
पुनर्निर्माण और समाजवादी कदम

जनवादी जन गणतंत्र कोरिया की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को युद्ध के कारण भारी नुकसान उठाना पड़ा था। उद्योग, कृषि और बिजली उत्पादन का स्तर काफी नीचे गिर गया था। अमेरिका की बमबारी से 8700 से अधिक फैक्ट्रियां नष्ट हो गई थीं। लोहे और कोयले की कई खदानें बरबाद हो गयी थी। अमेरिकी बमवर्षकों ने स्कूल, कॉलेज, अस्पताल सभी को अपना निशाना बनाया था।

उत्तरी कोरिया की मजदूर पार्टी तथा पार्टी के नेता किम इल-सुंग ने अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण और समाजवाद की नींव रखने के लिए भारी उद्योगों पर जोर देना प्रारम्भ किया।

अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में युद्ध पूर्व के उत्पादन स्तर को हासिल करने के लिए त्रिवर्षीय योजना (1954-1956) बनायी गयी। चीन, सोवियत संघ सहित पूरे समाजवादी खेमे ने उत्तरी कोरिया की मदद के लिए हाथ बढ़ाया।

त्रिवर्षीय योजना को दो वर्ष आठ माह में ही कोरिया की मेहनतकश जनता ने पूरा कर डाला।

1956 के अंत में सकल औद्योगिक उत्पाद 1953 के स्तर का 2.8 गुना तथा 1949 के स्तर 1.8 गुना तथा 1944 के स्तर का लगभग दो गुना हो चुका था।

इस काल के दौरान 280 से अधिक बड़े-छोटे उद्योगों का पुनर्निर्माण कर लिया गया जिनमें ह्वांगहाई आयरन वर्क्स, किमचाइक आयरन वर्क्स, सूपूंग पावर स्टेशन, प्योंगयांग टेक्सटाइल फैक्ट्री प्रमुख हैं। इन सभी उद्योगों का विस्तार भी कर दिया गया था।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भी बड़ी सफलताएं हासिल की गई। 1956 में अनाज उत्पादन युद्ध पूर्व की स्थिति से आठ प्रतिशत अधिक बढ़ गया था।

लोगों के जीवन स्तर में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई थी। फैक्ट्री मजदूरों, कार्यालय कर्मचारियों और किसानों की वास्तविक आय युद्ध पूर्व की स्थिति से भी अधिक हो चुकी थी।

युद्ध के समय उत्तरी कोरिया की राजधानी प्योंगयांग सहित अधिकांश शहर अमेरिकी बमबारी से पूरी तरह से नष्ट हो गये थे। प्योंङयांङ शहर में ऐसी कोई इमारत नहीं थी जो युद्ध में क्षतिग्रस्त न हुई हो। प्योंङयांग शहर में 428,900 से अधिक बम फेंके गये थे। पूरा प्योंङयांग शहर खण्डहर में तब्दील हो गया था। प्योंगयांग शहर दो वर्ष के भीतर ही एक तरह से राख में से पुनर्जीवित हो गया। वह भी आधुनिक और सुसज्जित ढंग से। इसी तरह से उत्तरी कोरिया के अन्य शहर भी मेहनतकशों ने आधुनिक ढंग से पुनर्निर्मित कर डाले। शहरीकरण ने तीव्र गति पकड़ ली थी। प्योंङयांङ की आबादी जहां युद्धकाल में 70 से 80 हजार के बीच थी वहीं नवम्बर 1954 आते-आते चार लाख हो चुकी थी।

कुल मिलाकर त्रिवर्षीय योजना की सफलता के बाद उत्तर कोरियाई समाज के आगे के विकास के लिए रास्ता चुनने का समय आ गया। उत्तरी कोरिया ने युद्ध समाप्त होने के तुरन्त बाद ही समाजवादी रास्ते की ओर कदम बढ़ा दिये थे। 5-9 अगस्त 1953 को पार्टी की केन्द्रीय कमेटी के छठे प्लेनम में पुनर्निर्माण और विकास की त्रिवर्षीय योजना रखने के साथ समाजवादी औद्योगीकरण की नींव को मजबूत करने के लिए उसके बाद पांच वर्षीय योजना रखी थी।

3 नवम्बर 1954 को कोरिया की मजदूर पार्टी की केन्द्रीय समिति के पूर्ण अधिवेशन में समापन भाषण देते हुए किम इल-सुंग ने 'कृषि के आगे के विकास के लिए हमारी पार्टी की नीति के सम्बन्ध में' कहा था,

" 2. गणतंत्र के उत्तरी आधे भाग के आर्थिक ढांचे और ग्रामांचल में समाजवादी रूपान्तर के सम्बंध में

"सबसे पहले मैं गणतंत्र के आधे उत्तरी भाग के आर्थिक ढांचे का विश्लेषण करना आवश्यक समझता हूं। जैसा कि सभी जानते हैं, हमारे देश के उत्तरी आधे भाग की अर्थव्यवस्था के तीन क्षेत्र हैं:

"पहला, समाजवादी राजकीय क्षेत्र

"दूसरा, सहकारिता क्षेत्र जिसका समाजवादी या अर्ध-समाजवादी चरित्र है;

"तीसरा, व्यक्तिगत क्षेत्र जिसमें पूंजीवादी और लघु माल उत्पादन की अर्थव्यवस्थाएं हैं।

"आइये, उद्योग और कृषि दोनों ही विषय में इन तीनों क्षेत्रों की स्थिति पर विचार करें।

"समाजवादी राजकीय क्षेत्र का उद्योग में....आधिपत्य है। यह परिणाम है जापानी साम्राज्यवादियों के उपनिवेशी शासन से देश की मुक्ति के बाद गणतंत्र के उत्तरी आधे भाग में मुख्य उद्योगों के राष्ट्रीयकरण का। हमारे उद्योग में समाजवादी आर्थिक नियम लागू हैं, क्योंकि यहां राजकीय आर्थिक क्षेत्र की सर्वोच्च सत्ता स्थापित है। फलतः हम उद्योग का निर्माण पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के नियमों के अनुसार नहीं, समाजवादी अर्थव्यवस्था के नियमों के अनुरूप कर रहे हैं।

"व्यक्तिगत क्षेत्र हमारे उद्योग का बहुत छोटा सा अंश हैं कुल औद्योगिक उत्पादन का लगभग 90 प्रतिशत भाग राजकीय स्वामित्व के उद्योग से प्राप्त होता है। शेष 10 प्रतिशत भाग में से 7-8 प्रतिशत भाग सहकारी अर्थतंत्र का है और व्यक्तिगत क्षेत्र का

अंश केवल 2-3 प्रतिशत है। युद्ध के पहले व्यक्तिगत अर्थतंत्र आज से बड़ा था। लेकिन युद्ध-काल में व्यक्तिगत व्यवसाय को बड़े घाटे हुए और व्यक्तिगत व्यवसायियों के लिए अपनी आर्थिक स्थिति का उद्धार करना बड़ा कठिन हो गया। अत: हमारे देश में अब व्यक्तिगत उद्यम बड़ी थोड़ी संख्या में हैं, जैसे चावल- मिलें, लुहारखाने और छोटे पैमाने की रबर फैक्टरियां। इसके अतिरिक्त देश के उत्तरी भाग में राजकीय और सहकारी उद्योगों पर व्यक्तिगत उद्यम का कोई प्रभाव होना तो दूर रहा, उल्टे वह इन दोनों के प्रभाव में और उन पर निर्भर करता है। ऐसा इसलिए है कि यातायात सुविधायें, बैंक, फैक्ट्रियां और उत्पादन के अन्य बड़े साधनों का राष्ट्रीयकरण किया जा चुका है और यहां जनसत्ता है जो मजदूर वर्ग के नेतृत्व में मजदूर-किसान की सुदृढ़ मैत्री पर आधारित है।

"इस कृषि में तीन आर्थिक क्षेत्रों की क्या स्थिति है?

"अधिकांश कृषि पर व्यक्तिगत स्वामित्व है। कृषि में लघु माल अर्थतंत्र अत्यधिक प्रभुत्वशाली है और अधिकांश व्यक्तिगत किसान खेती के बहुत पिछड़े हुए तरीके इस्तेमाल करते हैं।

"व्यक्तिगत अर्थतंत्र के अतिरिक्त कृषि मे सहकारी अर्थतंत्र भी है। **इस वर्ष पहली बार हमने प्रयोग रूप** में कृषि सहकारी समितियों को संगठित करना शुरू किया है। ये सहकारी समितियां तेजी से विकसित हो रही हैं और कुल किसान परिवारों के 21.5 प्रतिशत भाग इसमें शामिल हो चुके हैं।

"कृषि सहकारी समितियों के अतिरिक्त हमारे खेतीहर गांवों में अर्थतंत्र के समाजवादी स्वरूप भी हैं। वे हैं- राजकीय कृषि-पशुपालन फार्म और खेती की मशीनों तथा जोत-पशुओं को किराये पर देने वाले केन्द्र, उपभोक्ता सहकारी समितियां, किसान बैंक, ग्रामीण परिपूरक उत्पादन सहकारी समितियां, मछुआरों की सहकारी समितियां और राज्य संचालित सिंचाई सुविधायें जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के समाजवादी रूपान्तर की नींव का काम कर रहे हैं। इन सभी का स्वरूप समाजवादी या अर्ध-समाजवादी है। समाजवादी राज्य संचालित उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों पर बड़ा प्रभाव डालते हैं और समाजवादी तत्व ग्रामांचल में दिन-प्रतिदिन विकसित हो रहे हैं।

"सामान्यत: यही हमारे देश का आर्थिक ढांचा है।

"हमारा कर्त्तव्य है कि उद्योग और कृषि में समाजवादी क्षेत्र को धीरे-धीरे बढ़ायें और सुदृढ़ करें।" (किम इल-सुंग,'समाजवादी ग्रामीण प्रश्न के सम्बंध में' पृष्ठ 70-71-72, प्रकाशक अखिल भारतीय भारत कोरिया मैत्री संघ, नई दिल्ली, हिन्दी संस्करण 1976, जोर हमारा)

किम इल-सुंग का यह भाषण उत्तरी कोरिया के तत्कालीन आर्थिक ढांचे की समग्र तस्वीर प्रस्तुत कर देता है और कृषि क्षेत्र में समाजवादी कदम उठाने पर विशेष जोर देता है।

1957-61 के लिए बनायी गयी पंचवर्षीय योजना को सफलतापूर्वक ढाई वर्ष में ही पूरा कर लिया गया। सफलता की कहानी उत्साहजनक थी।

5 जनवरी, 1959 को कृषि सहकारी समितियों की राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रस्तुत रिर्पोट को 'समाजवादी कृषि सहकारीकरण की विजय और हमारे देश में कृषि के विकास का भविष्य' शीर्षक देते हुए किम इल-सुंग ने कहा,

"हमारी पार्टी के नेतृत्व में हमारी जनता ने युद्धोत्तर पुनर्वास और निर्माण में अगणित कठिनाइयों को पार कर एक स्वतंत्र अर्थतंत्र की नींव डाल दी है और गणतंत्र के उत्तरी आधे भाग में समाजवादी क्रांति के लिए निर्णयकारी विजय प्राप्त की है। इस आधार पर हमारे देश के समाजवादी निर्माण ने महान उत्थान के काल में प्रवेश किया है और पार्टी के आह्वान पर सारी जनता छोलिमा घुड़सवारों की तरह तेजी से आगे बढ़ रही है। समाजवादी निर्माण में सभी मोर्चों पर दुनिया को हिला देने वाले चमत्कार दिखाये जा रहे है और हर दिन भारी प्रगति की जा रही है।

"हमारे मजदूर वर्ग के वीरतापूर्ण श्रम के फलस्वरूप भारी संख्या में आधुनिक प्रविधि से लैस फैक्ट्रियों और उद्यमों का एक के बाद एक निर्माण हो रहा है और उद्योगों की उत्पादक शक्तियां दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही हैं। 1957 में हमारे देश का औद्योगिक उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में 44 प्रतिशत अधिक था और 1958 में 1957 के उत्पादन की तुलना में 40 प्रतिशत और वृद्धि हुई। पिछले वर्ष हमारे मजदूरों ने युद्ध से पहले के वर्ष 1949 की तुलना में 3.7 गुना अधिक औद्योगिक सामान तैयार किया। ...

"हमारी पार्टी के नेतृत्व में किसानों ने कृषि की उत्पादक शक्तियों की बहाली और विकास के क्षेत्र में अभी ही काफी कुछ उपलब्ध कर लिया है। और कृषि का समाजवादी सहकारीकरण पूरा कर दिया है। आज हमारे किसान देहातों में तकनीकी और सांस्कृतिक क्रांति पूरी कर उनको एक समृद्ध और सुसंस्कृत, आधुनिक प्रविधि से लैस समाजवादी क्षेत्र बनाने का प्रयास कर रहे हैं।...

"फलत:, हमारे देश में कृषि सहकारिता आंदोलन अगस्त 1958 के अंत तक पूर्णतया विजयी हो गया। यह ग्रामीण क्षेत्रों में एक महान क्रांति थी और हमारी पार्टी की कृषि नीति की शानदार जीत थी।

"1958 में देहातों को सप्लाई की गयी रासायनिक खाद 1953 की तुलना में 12 गुना अधिक थी और खेती की मशीनों तथा औजारों की संख्या भी तेजी से बढ़ी। साथ ही, किराये पर खेती की मशीनें देने वाले केन्द्रों की संख्या भी बढ़ायी गयी और ट्रैक्टरों की संख्या भी 4 गुनी बढ़ी (15 अश्वशक्ति इकाइयों की दृष्टि से) जिनके फलस्वरूप ट्रैक्टरों द्वारा जोती बोयी जमीन का क्षेत्रफल 12 गुना बढ़ा।

"1956 में ही अनाज का उत्पादन 28,70,000 टन हो गया जिससे युद्ध पूर्व का स्तर पार हो गया और 1957 में वह 32,00,000 टन तथा 1958 में 37,00,000 टन तक बढ़ गया। 1958 का अनाज उत्पादन 1946 यानी ठीक मुक्ति के बाद के वर्ष की तुलना में दो गुना हो गया। ...

"फलतः 13,309 कृषि सहकारी समितियों का 3,843 समितियों (प्रत्येक प्रशासकीय री में कृषि सहकारी समितियों का एक समिति में विलय- लेखक) में विलय हो गया और उनका औसत आकार 80 से 300 किसान परिवारों का और 130 से 500 छोंङ बो कृषि भूमि तक का हो गया। ...

"हम अब एक उन्नत समाजवादी व्यवस्था में रह रहे हैं। हमारा देश अब एक पिछड़े हुए कृषि प्रधान राज्य से एक समाजवादी औद्योगिक-कृषि राज्य के रूप में बदल गया है।" (पृष्ठ 86-121, वही)

कृषि में सहकारिता आंदोलन के 1958 में पूरा होने से वास्तव में समाजवादी उत्पादन सम्बंधों को उत्तरी कोरिया के समाज में स्थापित करने में एक बड़ा कदम उठाया जा चुका था।

1958 में शुरू किये गये छोलिमा आंदोलन ने भारी संख्या में पूरे देश में मजदूरों, किसानों तथा अन्य नागरिकों को तीव्र गति से देश के औद्योगीकरण तथा सहकारीकरण के लिए प्रेरित किया। छोलिमा कोरियाई मिथक का एक ऐसा पंख युक्त अश्व है जो कि एक दिन में 1000 री (10 री बराबर लगभग 4 किमी) की दूरी तय कर सकता है। पंख युक्त इस अश्व के लिए ऊंचे-ऊंचे पहाड़ और मैदान कुछ मायने नहीं रखते हैं। वह एक छलांग में एक पहाड़ लांघ सकता है। वास्तव में कोरियाई जनता ने छोलिमा आंदोलन के दौरान इस मिथकीय अश्व की गति से औद्योगीकरण और सहकारीकरण किया जो कि तथ्यों से सुस्पष्ट है। सम्बन्धित तालिकायें देखें।

तालिका 1: कुल सामाजिक उत्पाद की संरचना (प्रतिशत में)

	1956	1969
औद्योगिक और कृषि उत्पादन	100	100
उद्योग का हिस्सा	34.0	74.0
कृषि का हिस्सा	66.0	26.0

[स्रोत : पृष्ठ 394, Great Soviet Encyclopedia, MACMILLAN, INC, New York Vol. 13, Third Edition, Moscow Sovetskaia Entsiklopediia Publishing house,1973]

तालिका 2: मुख्य औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन

औद्योगिक उत्पाद	1949	1960	1970
विद्युत शक्ति (अरब किलोवाट घण्टा)	5.9	9.1	16.5
कोयला (दस लाख टन में)	4.0	10.6	27.5
ढलावां लोहा (टन में)	200,000	900,000	2,400,000
इस्पात (टन में)	100,000	600,000	2,200,000
मेटल कटिंग टूल्स (इकाई)	-	2,900	6,400
ट्रैक्टर (संख्या में)	-	3,000	10,000
मोटर गाड़िया (संख्या में)	-	3,100	6,400
खनिज खाद (टन में)	400,000	600,000	1,500,000
सीमेंट (टन में)	500,000	2,300,000	4,000,000
कागज (टन में)	17,000	47,000	128,000*
कपड़ा (दस लाख मीटर में)	12.3	189.7	400

[*- 1969 के आधार पर] [स्रोत : पृष्ठ 395, तालिका संख्या 2, वही]

तालिका 3: प्रमुख कृषि फसलों की पैदावार (टन में)

	1946-49*	1953-56*	1957-60*	1970 (अनुमान)
धान	1,165,000	1,222,000	1,476,000	3,000,000
अनाज	264,000	413,000	1,045,000	1,500,000
सोयाबीन	179,000	190,000	225,000	400,000
हरी सब्जियां	610,000	826,000	1,630,000	3,000,000
आलू	509,00	529,000	760,000	1,000,000

[*- वार्षिक औसत] [स्रोत : तालिका 3, पृष्ठ 395, वही]

तालिका 4: पशुधन का उत्पादन

	1949	1960	1966
मवेशी **(cattle)**	**788,000**	**672,000**	**740,000**
भेड़े	**10,000**	**105,000**	**185,000**
बकरियां	**3,000**	**79,000**	**240,000**
सुअर	**660,000**	**1,123,000**	**1,640,000**

[स्रोत : तालिका **4, पृष्ठ 395,** वही]

1966 में जनवादी जन गणतंत्र कोरिया की सर्वोच्च जन संसद (Supreme People's Assembly) द्वारा एक कानून के जरिये सहकारी समितियों से राज्य द्वारा जिन्स के रूप में जारी कर प्रणाली को समाप्त कर दिया गया तथा ग्रामीण पूंजीगत निर्माण परियोजनाओं का खर्च पूरी तरह से राज्य उठाने लगा।

इसके बारे में किम इल-सुंग ने 25 फरवरी 1964 को कोरिया की मजदूर पार्टी की चौथी केन्द्रीय समिति के आठवें पूर्ण अधिवेशन में स्वीकृत 'हमारे देश के समाजवादी ग्रामीण प्रश्न के सम्बंध में', थीसिस में कहा,

"... अब चूंकि देश में उद्योग की शक्ति बढ़ गयी है और देश के स्वाधीन देश के अर्थतंत्र की नींव अधिक मजबूती से रखी जा चुकी है। इसलिए हम सहकारी फार्मों और किसानों का भार कम करने और राजकीय खर्च पर उन्हें और लाभ दे पाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं। ये कदम हैं:

"प्रथम, जिंस के रूप में कृषि कर प्रणाली की पूर्ण समाप्ति;

"दूसरा, भविष्य में उन ग्रामीण पूंजीगत निर्माण परियोजनाओं का खर्च राजकीय कोष से पूरा करना जिनमें अब तक सहकारी फार्मों का धन लगता था;

"तीसरा, राजकीय खर्च पर किसानों के लिए आधुनिक मकानों का निर्माण

"1- जिन्स के रूप में कृषि कर प्रणाली की समाप्ति

"हमारे देश में जिन्स के रूप में कृषि कर प्रणाली की शुरूआत 1946 में- मुक्ति के तुरन्त बाद वाले वर्ष में- भूमि सुधारों के समय हुई थी।

"मुक्ति से पहले किसानों की अधिकांश फसल भू स्वामी तथा जापानी साम्राज्यवादी खेती की लगान, जबरन वसूली और अन्य कठोर करों और वसूलियों के रूप में लूट लेते थे। भूमि सुधारों के लागू होने और जिन्स कर व्यवस्था के शुरू होने से किसानों को ऐसे शोषण और लूट से मुक्ति मिल गयी और केवल 25 प्रतिशत राज्य को देने के बाद अपनी फसल को स्वतंत्र रूप से बेचने की आजादी मिल गयी। उस समय हमारी कृषि की उत्पादक शक्तियों के विकास में और किसान समुदाय का जीवन स्तर उठाने में यह एक क्रांतिकारी परिवर्तन था। ...

"जैसे-जैसे समाजवादी राजकीय उद्योग प्रगति करते गये और स्वतंत्र राष्ट्रीय अर्थतंत्र की नींव रखी गयी, राज्य क्रमश: किसानों पर जिंस के रूप में लगाये गये कर के भार को कम करता गया। युद्ध के बाद जिंस कर की दर फसल के 25 प्रतिशत से घटकर औसतन 20.1 प्रतिशत कर दी गयी और 1959 में और भी घटाकर 8.4 प्रतिशत कर दी गयी। इसके अलावा अनेक सहकारी फार्मों पर जिंस कर कम कर दिया गया और कुछ को इससे बिल्कुल छूट दे दी गयी। 1963 के अंत तक हमारे 3,700 से अधिक सहकारी फार्मों में से 1,331 को पूरी तरह छूट दे दी गयी थी।

"हमारी पार्टी की चौथी कांग्रेस ने फैसला किया कि सात वर्षीय योजना के दौरान जिंस कृषि कर को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाना चाहिए।

" 2- राजकीय खर्च पर समस्त पूंजीगत निर्माण

..."अब तक बड़े पैमाने की समस्त ग्रामीण पूंजीगत निर्माण परियोजनाओं में राज्य का धन लगता रहा है तथा मझोली और छोटे पैमाने की परियोजनाओं का खर्च और निर्माण कार्य मुख्यत: स्वंय सहकारी फार्म पूरा करते रहे हैं। पिछले पांच वर्षों में राज्य ने देहातों में कुल 60 प्रतिशत से अधिक पूंजी निवेश किया और सहकारी फार्मों ने शेष लगभग 40 प्रतिशत जुटाया।

"इस वर्ष से हमें वह पूंजीगत निर्माण कार्य राज्य के खर्च पर करना चाहिए जिसे पहले सहकारी फार्म अपने धन से करते थे।...

(पृष्ठ-39-40-41,वही)

11 अक्टूबर, 1969 को किम इल सुंग ने पार्टी और राज कार्यकर्ताओं के बीच भाषण 'हमारे देश में जनवादी और समाजवादी क्रांतियों के कुछ अनुभव के सम्बंध में' में कहा,

"कोरिया की मजदूर पार्टी के बुद्धिमत्तापूर्ण नेतृत्व में हमारे देश की जनता ने जनवादी और समाजवादी क्रांतियों को सफलतापूर्वक सम्पन्न किया है और उसने बहुमूल्य अनुभव प्राप्त किये है तथा अनेक सबक सीखे हैं। ... (पृष्ठ -266, पैरा-1, वही)

"हमने निस्सन्देह अल्पकाल में मुक्ति के बाद 25 साल से कम समय में ही काफी काम किया है। हमारी पार्टी ने एक समय के औपनिवेशिक अर्धसामंती समाज को सुदृढ़, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था तथा भव्य राष्ट्रीय संस्कृति सहित एक शक्तिशाली, विकसित, समाजवादी राज्य के रूप में अपने देश को बदलने में जनता का नेतृत्व किया।" (पृष्ठ-288, पैरा-3 वही)

कुल मिलाकर, उत्तरी कोरिया ने समाजवादी राह को पकड़ कर एक औपनिवेशिक अर्धसामंती समाज को क्रमशः समाजवादी राज्य की ओर उस समय बढ़ाया जिस समय अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट आंदोलन में खुश्चेव के नेतृत्व में संशोधनवाद तेजी से अपना असर दिखा रहा था। उत्तरी कोरिया के समाजवादी रास्ते में गम्भीर चुनौतियां मौजूद थीं। उत्तरी कोरिया के समाजवाद को सबसे गम्भीर चुनौती अंदर से ही मिली। इसकी आगे चर्चा की गयी है।

V
समाजवाद और जूछे विचारधारा

किम इल-सुंग ने पहले-पहल जूछे की बात 28 दिसम्बर 1955 को पार्टी के प्रचारकों तथा उद्वेलकों के सामने कही थी। जूछे एक कोरियाई शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ हिन्दी के शब्द आत्मनिर्भरता (Self-Reliance) के सबसे करीब है।

जूछे विचार को विचारधारा के स्तर तक विकसित होने के लिए एक लम्बी यात्रा करनी थी। किम इल-सुंग का 1955 में जूछे से मूलतः आशय इस बात से था कि कोरियाई कम्युनिस्ट किसी अन्य देश की क्रांति की नकल करने के स्थान पर कोरियाई समाज की विशिष्ट परिस्थिति को देखते हुए मार्क्सवाद-लेनिनवाद का स्वतंत्र रूप से प्रयोग करें। जड़सूत्रवाद या पिछलग्गूपन के शिकार न हों। शुरू में दिये गये भाषणों से कम से कम यह आशय नहीं निकलता कि किम इल-सुंग मार्क्सवाद-लेनिनवाद के समानान्तर जूछे विचारधारा या किम इल-सुंगवाद जैसी कोई चीज प्रस्तुत कर रहे हैं।

28 दिसम्बर 1955 को दिये गये भाषण का शीर्षक है, 'जड़सूत्रवाद तथा औपचारिकतावाद को खत्म करने तथा विचारधारात्मक कार्य के स्तर पर जूछे को स्थापित करने के बारे में' (On eliminating dogmatism and formalism and establishing Juche in ideological Work)। इस भाषण में किम इल-सुंग ने कहा,

" हमारी पार्टी के विचारधारात्मक कार्य में जूछे क्या है? हम क्या कर रहे हैं? हम किसी अन्य देश की क्रांति में नहीं बल्कि कोरियाई क्रांति में लगे हुए है। इसलिए बिल्कुल कोरियाई क्रांति के लिए हमारे पार्टी का विचारधारात्मक कार्य **जूछे** से निर्मित हो। इसलिए बिना किसी अपवाद के सारे विचारधारात्मक कार्य को कोरियाई क्रांति के हितों के अधीन होना चाहिए।"

(पृष्ठ 479, किम इल-सुंग का उद्धरण,[Kim IL Sung Biography (II)by Baik Bong, वही,जोर मूल में, अनुवाद हमारा]

और आगे देशभक्ति तथा अन्तर्राष्ट्रीयतावाद के संदर्भ में किम इल-सुंग कहते हैं,

"... देशभक्ति तथा अन्तर्राष्ट्रीयतावाद आपस में अविभाज्य हैं। जो कोई अपने देश को प्यार नहीं करता वह अन्तर्राष्ट्रीयतावाद के प्रति वफादार नहीं हो सकता है और जो कोई अन्तर्राष्ट्रीयतावाद के प्रति निष्ठावान नहीं है वह अपने देश और जनता के प्रति भी निष्ठावान नहीं हो सकता है। एक सच्चा देशभक्ति ही अन्तर्राष्ट्रीयतावादी है और इसका उल्टा भी।"

(पृष्ठ 480-481, अनुवाद हमारा)

1956 में ख्रुश्चेव द्वारा सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की बीसवीं कांग्रेस में संशोधनवादी विचार रखे जाने के बावजूद 1963 तक भारी मतभेदों के साथ दुनिया में एक समाजवादी खेमा मौजूद था। 1963 में खेमे में फूट पड़ने तक किम इल-सुंग के लिए इस बात की कोई आवश्यकता नहीं थी कि वे किसी एक पक्ष को चुनें या सोवियत संशोधनवादियों व चीनी क्रांतिकारियों से समान दूरी बनाते हुए स्वतंत्र रास्ते पर चलें। पक्ष चुनने या मध्यम मार्ग के स्वतंत्र रास्ते पर चलने का सवाल किम इल-सुंग के सामने आगे आना था।

5 जनवरी, 1959 में वे कह रहे थे,

"आज समाजवाद विश्वव्यापी पैमाने पर विजय प्राप्त कर रहा है और साम्राज्यवादी शक्तियां द्रुतगति से अपनी मौत के मुंह में जा रही हैं।

"समाजवादी खेमा साम्राज्यवादी खेमे से अतुलनीय रूप से अधिक शक्तिशाली है। समाजवादी खेमे में पृथ्वी की भूमि का एक चौथाई भाग है और उसमें 100 करोड़ से अधिक आबादी रहती है जो साम्राज्यवादी देशों की आबादी से दोगुनी है। ...

"सभी लोक जनतंत्रों में समाजवाद का सफलतापूर्वक निर्माण हो रहा है, उनके राष्ट्रीय अर्थतंत्र तेजी से विकसित हो रहे हैं और उनकी जनता के रहन-सहन के स्तर में लगातार सुधार हो रहा है।

"इस समय समाजवादी खेमे के देश दुनिया के औद्योगिक उत्पादन का एक-तिहाई भाग पैदा कर रहे हैं और अगले सात वर्षों में आधे से अधिक उत्पादन करने लगेंगे।

"मार्क्सवाद-लेनिनवाद और सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रीयतावाद के झण्डे के नीचे समाजवादी खेमे के देश और भी दृढ़ता से एकताबद्ध हो गये हैं।

"इस सब से समाजवादी खेमे की अजेय शक्ति प्रदर्शित होती है जो साम्राज्यवादी शक्तियों पर हावी हो रही है। ...

"बिरादराना देशों के जनगण के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारी जनता अपने देश में समाजवाद का विजय पूर्वक निर्माण करेगी और अपने देश का निश्चय ही पुनर्एकीकरण करेगी। इस प्रकार हमारी जनता सुदूर पूर्व में और सारी दुनिया में शान्ति को तथा समाजवाद की स्थितियों को और अधिक सुदृढ़ करने में योगदान करेगी।"

(किम इल-सुंग, 5 जनवरी 1959, 'समाजवादी कृषि सहकारीकरण की विजय और हमारे देश में कृषि का भविष्य, पृष्ठ 131, वही)

1963 के बाद से किम इल-सुंग का जोर धीरे-धीरे इस बात पर बढ़ने लगा था कि पार्टी के कार्यकर्ता और जनता जूछे विचार से अपने आपको लैस करें। परन्तु अभी ऐसा नहीं हुआ था कि वे मार्क्सवाद-लेनिनवाद की चर्चा न करें। 1974 तक भी किम इल-सुंग मार्क्सवाद-लेनिनवाद का लगातार उल्लेख करते थे। बाद के वर्षों में बस ये होने लगा कि जूछे विचार को इस रूप में प्रस्तुत किया जाने लगा कि कोरियाई परिस्थिति में मार्क्सवाद-लेनिनवाद जूछे विचार है। अब अक्सर ही किम इल-सुंग जूछे विचार के अध्ययन पर विशेष जोर देने लगे। अब शीघ्र ही वह समय आने वाला था जब जूछे विचार को विचारधारा का दर्जा दिया जाने वाला था। आइये, उस जगह तक पहुंचने से पहले किम इल-सुंग के अलग-अलग समय पर दिये गये कुछ वक्तव्यों पर गौर करें।

11 अक्टूबर 1969 को पार्टी और राज्य कार्यकर्ताओं के बीच भाषण में वे कहते हैं,

"हमारी पार्टी ने जनवादी क्रांति तथा समाजवादी क्रांति और समाजवादी निर्माण के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के जो अनुभव अर्जित किये हैं, उनके आधार पर पुस्तकों को तैयार करना चाहिए। ... **इन पुस्तकों में पार्टी के 'जूछे विचार' की विवेचना पूर्ण रूप से होनी चाहिए।**" (किम इल-सुंग, 'जनवादी और समाजवादी क्रांति के कुछ अनुभव, पृष्ठ-289-290, वही, जोर हमारा)

25 दिसम्बर, 1972 को 'जनवादी जन गणतंत्र कोरिया की पांचवीं सर्वोच्च जन संसद के प्रथम अधिवेशन में दिये गये भाषण' में किम इल-सुंग ने समाजवादी व्यवस्था को सुदृढ़ करने का तो आह्वान किया परन्तु मार्क्सवाद-लेनिनवाद की उस तरह से चर्चा नहीं की जैसे वे दस वर्ष पहले कर रहे थे। उन्होंने कहा,

"गणतंत्र की सरकार को विचारधारात्मक क्रांति तेजी से आगे बढ़ानी चाहिए और पार्टी की सुंसगत नीति के अनुसार पूरे समाज को क्रांतिकारी चेतना और मजदूर वर्ग की भावना से अनुप्राणित कर देना चाहिए।

"समस्त समाज की क्रांतिकारी चेतना और मजदूर वर्ग की भावना से अनुप्राणित करने में सबसे **महत्वपूर्ण कार्य है** मेहनतकश जनता को हमारी पार्टी के अविकल विचार, जूछे विचार से लैस करना। हमारी पार्टी का **जूछे विचार ही कोरियाई क्रांति के सफल कार्यान्वयन का एकमात्र पथप्रदर्शक है।** मेहनतकश जनता इस विचार से पक्के तौर पर लैस होकर ही **एक क्रांतिकारी विश्वदृष्टिकोण रख सकती है** और क्रांतिकारी संघर्ष और निर्माण कार्य में अपने कर्त्तव्य को प्रशंसनीय ढंग से पूरा कर सकती है। मेहनतकश जनता की हमारी पार्टी के अविकल विचार, **जूछे विचार से लैस करने के लिए** पार्टी नीतियों और क्रांतिकारी परम्पराओं में उसकी शिक्षा को सघन बनाना चाहिए और इस प्रकार उन सभी को पार्टी का ऐसा सच्चा लाल योद्धा, कम्युनिस्ट क्रांतिकारी बनने को प्रशिक्षित करना चाहिए जो किसी भी विकट परिस्थिति में क्रांतिकारी सिद्धान्तों की रक्षा करें और पार्टी की लाइनों और नीतियों पर अमल करें।

"जूछे विचार से उन्हें लैस करते हुए हमें मेहनतकश जनता में वर्ग शिक्षा को मुख्य अंतर्वस्तु बनाकर कम्युनिस्ट शिक्षा को सघन बनाना चाहिए ..." (किम इल-सुंग, 'आइए, हम अपने देश की समाजवादी व्यवस्था को और सुदृढ़ करें', पृष्ठ 325-326, वही)

और इस तरह से स्पष्ट है कि किम इल-सुंग का जोर जूछे विचार पर बढ़ता जा रहा था। मार्क्सवाद-लेनिनवाद की चर्चा अब भी वो करते थे परन्तु उसकी व्याख्या में तथा उसके आधार पर कोरियाई क्रांति को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा फर्क आ चुका था। राष्ट्रवाद और साम्यवाद किम इल-सुंग के लिए अंत:परिवर्तनीय शब्द और विचार बनते जा रहे थे।

जूछे विचार क्या है? इस विषय पर व्यापक प्रकाश किम इल-सुंग ने 17 सितम्बर 1972 को जापान के कुछ पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए डाला था। सवालों का जवाब देते हुए किम इल-सुंग ने 'समाजवादी खेमे' की एकता पर जोर देते हुए जो अवस्थिति ग्रहण की वह अपने गहरे अर्थ में गैर मार्क्सवादी-लेनिनवादी थी। अपनी राष्ट्रीय आवश्यकताओं से उपजी यह नीति सामाजिक-साम्राज्यवादी सोवियत संघ और सांस्कृतिक क्रांति कर रहे चीनी समाजवाद को एक ही खेमे में रख देती थी। घोर अवसरवाद से युक्त यह नीति इस बात की परिचायक थी कि विचारधारात्मक या सैद्धान्तिक प्रश्नों पर दृढ़ क्रांतिकारी अवस्थिति न ग्रहण करने और मध्यम मार्ग अपनाने या 'एकता-एकता' की सिद्धान्तविहीन चीख-पुकार मचाने का अंतत: नतीजा यही निकलता है कि ऐसी अवस्थिति ग्रहण करने वाले व्यक्ति, पार्टियां संशोधनवाद के रास्ते पर चल पड़ती हैं और सर्वहारा वर्ग की विचारधारा और ध्येय से गद्दारी कर देती हैं।

किम इल-सुंग के जापानी पत्रकारों को दिये गये जवाब क्योंकि अत्यंत महत्वपूर्ण हैं इसलिए हम उसके एक बड़े हिस्से को प्रस्तुत कर रहे हैं। किम इल-सुंग जवाब देते हुए कहते हैं,

"आपने मुझसे अनुरोध किया है कि यह बतायें कि जूछे विचार कैसे उत्पन्न हुआ।

"संक्षेप में, जूछे का अर्थ है कि क्रांति और निर्माण के कार्य की स्वामी व्यापक जनता है और वे ही क्रांति और निर्माण कार्य की उत्प्रेरक शक्ति हैं। दूसरे शब्दों में हर कोई अपनी नियति के लिए जिम्मेदार है और अपनी नियति को तय करने की क्षमता हर किसी में होती है।

"हम इस विचार के जनक नहीं हैं। हर मार्क्सवादी-लेनिनवादी के पास यह विचार है। मैने **इस विचार पर सिर्फ जोर दिया है।**

"यह लोगों और किसी देश विशेष की सामाजिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर निर्भर करता है कि **जूछे की स्थापना** की आवश्यकता कितनी तीव्रता से महसूस की जा सकती है और उस पर कितना जोर दिया जाता है।

"हमारे देश की मुक्ति तथा स्वतंत्रता के लिए जो संघर्ष मैंने किया उस दौरान मेरी यह दृढ़ आस्था बनी कि हमें अपने ही प्रयासों से अपनी नियति तय करनी होगी और ऐसा हम कर सकते हैं। हमारा संघर्ष जटिल और कठिन था। हमें हर चीज स्वयं हल करनी थी और संघर्षों में तरीकों व कार्यदिशाओं का सूत्रीकरण भी स्वयं अपना दिमाग इस्तेमाल करके करना था। ...

"हमारे अनुभव ने यह दिखाया है कि इस तरीके से अपनी समस्याओं को हल करना हमारी वास्तविक स्थितियों के लिए उससे कहीं अच्छा था यदि हम यांत्रिक ढंग से विदेशी तौर-तरीकों की नकल करते। एक नये देश के निर्माण के लिए आजादी के बाद के हमारे संघर्ष ने जूछे विचार को सही साबित किया है और उसमें हमारी आस्था को बढ़ाया है।...

"इस मार्क्सवादी-लेनिनवादी धारणा से प्रस्थान करते हुए कि सहकार, भले ही वह आदिम तकनीक पर आधारित हो, निजी खेती से कहीं बेहतर होता है और इस वास्तविक तथ्य को संज्ञान में लेते हुए कि किसानों को अपनी दरिद्रता से मुक्त होने के लिए मिलकर काम करने की जबरदस्त जरूरत है, हमने एक बिल्कुल मौलिक तरीका अपनाया- हमने औद्योगीकरण के पहले ही कृषि के समाजवादी रूपान्तरण की दिशा में दृढ़तापूर्वक कदम बढ़ाये। जहां तक छोटे और मझोले उद्यमियों और धनी किसानों का प्रश्न है वहां भी हमने **अनूठा तरीका** अपनाया- हमने उन्हें भी सहकारी समितियों में समेटा और समाजवादी दिशा में उनका रूपान्तरण किया क्योंकि उनका सम्पत्तिहरण करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं थी। ...

"हमारी क्रांति एक बहुत जटिल और दुरूह रास्ते से गुजरी है और आज भी गुजर रही है। जब-जब हमारे सामने समस्यायें और विपत्तियां आई तब-तब हमने क्रांति के स्वामी का दृष्टिकोण अपनाया और इस प्रक्रिया ने हमारी आस्था को और पुख्ता किया–यह आस्था कि जूछे विचार पर दृढ़तापूर्वक आधारित होने से मजदूर वर्ग अपनी क्रांतिकारी अवस्थिति कायम रख सकता है और हमारे देश की वास्तविक स्थितियों के अनुरूप मार्क्सवाद-लेनिनवाद को सृजनात्मक ढंग से लागू किया जा सकता है।

"आपने मुझसे जानना चाहा है कि क्या आप यह समझें कि जूछे विचार **राजनीति में स्वतंत्रता**, **अर्थव्यवस्था में स्वावलम्बन** और **राष्ट्रीय सुरक्षा में आत्म सुरक्षा है।** आपकी समझदारी काफी कुछ ठीक है।

"जूछे की स्थापना का मतलब है क्रांति और निर्माण के प्रति स्वामी का दृष्टिकोण अपनाया जाय। क्योंकि क्रांति और निर्माण के स्वामी व्यापक जन हैं। अतः क्रांति और निर्माण के प्रति एक जिम्मेदार स्वामी का दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। स्वामी का दृष्टिकोण एक स्वतंत्र और सृजनात्मक अवस्थिति में अभिव्यक्त होता है।

"....स्वतंत्रता ही वह चीज है जो मनुष्य को जिंदा रखती है। यदि वह समाज में स्वतंत्रता खो देता है तो उसे मनुष्य नहीं कहा जा सकता; वह पशु जैसा ही हो जाता है। हम कह सकते हैं कि सामाजिक-राजनीतिक जीवन किसी मनुष्य के लिए भौतिक जीवन से ज्यादा मूल्यवान है। वह एक सामाजिक प्राणी है। यदि उसे समाज द्वारा तिरस्कृत और राजनीतिक स्वतंत्रता से वंचित कर दिया जाता है तब यद्यपि वह जिंदा होता है तथापि एक सामाजिक मानव के रूप में मृतप्रायः ही है।.....

"अपनी नियति का स्वामी होने के लिए किसी राष्ट्र के पास एक स्वतंत्र सरकार होनी चाहिये और उसकी **राजनीतिक स्वतंत्रता पूर्णतया** सुनिश्चित होनी चाहिये। यही कारण है कि जूछे विचार में सर्वप्रथम राजनीति में स्वतंत्रता के सिद्धान्त को शामिल किया जाना चाहिए। ...

"देश की स्वतंत्रता को सुदृढ़ करने के लिए यह जरूरी है कि राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ-साथ अर्थव्यवस्था में आत्मनिर्भरता सुदृढ़ की जाय। अर्थव्यवस्था में आत्मनिर्भरता के बगैर जनता की बढ़ती हुई भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करना असम्भव है और समाज व राजसत्ता के स्वामी की उनकी वास्तविक भूमिका को भौतिक अर्थों में सुनिश्चित करना असम्भव है। दूसरों पर आर्थिक निर्भरता की स्थिति में राजनीतिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता और एक स्वतंत्र शक्ति बने बगैर राष्ट्रीय प्रतिरक्षा के मामले में आत्म रक्षा की कार्य दिशा लागू करना असम्भव है। ...

"जूछे विचार का आधार यह है कि **मनुष्य सभी चीजों को स्वामी है** और **हर चीज में निर्णायक तत्व है।** प्रकृति और समाज का पुनर्निर्माण लोगों के लिए है और उनके द्वारा किया जाने वाला कार्य है। मनुष्य दुनिया का सबसे अनमोल खजाना है और वही सबसे शक्तिशाली भी है। ...

" आपने मुझसे पूछा है कि हमारी विदेश नीति जो कि जूछे-विचार पर आधारित है की समाजवादी देशों के भाई चारे को मजबूत करने, साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय जनवादी शक्तियों को सुदृढ़ करने में, क्या भूमिका है?...

"स्वतंत्रता के बिना कोई अंतर्राष्ट्रीयतावाद नहीं हो सकता और इसका उलटा भी सच है। ...

"सर्वप्रथम हमारी सरकार की विदेश नीति जूछे विचार पर आधारित है। यह समाजवादी देशों के भाई चारे को मजबूत करने में सक्रिय योगदान करती है।

" समाजवादी देशों के बीच एकता और नजदीकियां बढ़ाने के अपने प्रयासों में हम स्वतंत्रता के अपने सिद्धान्त पर कायम रहते हैं। हमारी **अवस्थिति है कि सभी समाजवादी देशों को सर्वप्रथम साम्राज्यवाद का विरोध करना चाहिए, दूसरा,** उपनिवेशों में राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन तथा अंतर्राष्ट्रीय मजदूर आंदोलन का समर्थन करना चाहिए; तीसरा; समाजवाद और साम्यवाद की ओर बढ़ना चाहिए; चौथा, एक-दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने के सिद्धान्त के आधार पर एकता हासिल करनी चाहिए। यद्यपि बिरादर पार्टियों ओर समाजवादी देशों के बीच मतभेद हैं तब भी हम इन चार सिद्धान्तों के आधार पर एकता को प्रोत्साहित करते हैं और संयुक्त संघर्ष में शामिल होते हैं।" (किम इल-सुंग,

"On some problem's of our party's Juche idea and the government of the republic's internal and external Policies Answer to the questions raised by jurnalists of the Japanese News paper, Mainichi Suimbun, September 17, 1972, किम इल-सुंग, के लेखों के संकलन For the independent peaceful Reunification of the country, पृष्ठ-207 से 220, F.L.P.H. Pyongyang, Korea, 1976 अनुवाद हमारा, जोर हमारा)

इस लंम्बे उद्धरण से बहुत साफ तौर पर स्पष्ट हो जाता है कि किम इल-सुंग किस रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे। 1972 और उसके बाद किम इल-सुंग के लेखों वक्तव्यों और भाषणों में ये अवस्थितियां और मजबूत होती चली गयीं।

इन अवस्थितियों में निम्न बातें महत्वपूर्ण हैं। पहली, कि किम इल-सुंग ने मार्क्सवाद-लेनिनवाद की कई सुस्थापित अवधारणाओं तथा अवस्थितियों की ऐसी व्याख्यायें प्रस्तुत करनी शुरू कर दी थीं जो अपने चरित्र में वर्गेतर हैं। जूछे विचार में सर्वहारा का स्थान एक अमूर्त जनता ने ले लिया है और यह सुस्थापित धारणा कि सर्वहारा वर्ग दुनिया का सबसे क्रांतिकारी वर्ग है और इस वर्ग में ही यह क्षमता है कि वह समाज को वर्ग विहीन समाज की ओर, साम्यवाद की ओर ले जा सकता है, के स्थान पर इस तरह की बातें की जाने लगीं कि 'मनुष्य ही सब चीजों का स्वामी है और वही हर चीज में निर्धारक तत्व है'। जूछे विचार से लैस यह 'मनुष्य' सबसे शक्तिशाली है जो प्रकृति और समाज को अमूर्त जनता के हित में बदल सकता था। यहां ऐतिहासिक-भौतिक परिस्थितियां कोई खास अर्थ नहीं रखती हैं, यहां 'मनुष्य' है जो सब चीजों को स्वामी है।

एक अन्य चीज जिस पर किम इल-सुंग का बहुत जोर है वह 'सवतंत्रता' है। 'स्वतंत्र अवस्थिति' 'राजनीति में स्वतंत्रता' की गारण्टी है। जूछे विचार अपने आपको सबसे पहले राजनीतिक स्वतंत्रता के सिद्धान्तों के रूप में मूर्त रूप देता है। राजनीतिक स्वतंत्रता का यह आलाप जहां किम इल-सुंग को एक तरफ राष्ट्रवादी भटकावों की ओर ल जाता है तो दूसरी तरफ यह अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट आंदोलन में उस समय जारी क्रांतिकारी दिशा और संशोधनवादी दिशा के बीच जारी संघर्ष से किनाराकशी का साधन बन जाता है।

किम इल-सुंग राजनीतिक स्वतंत्रता बनाये रखने के सिद्धान्त के कुछ मामलों में तो विशेष रूप से पक्के हैं। जैसे सोवियत सामाजिक-साम्राज्यवादियों के भारी दबाव और धमकियों के बावजूद वे कभी भी 'पारस्परिक आर्थिक सहायता परिषद (कॉमेकॉन) के सदस्य नहीं बने। कॉमेकॉन एक ऐसी संस्था थी जिसके माध्यम से सोवियत साम्राज्यवादी अपने हितों को साधते थे तथा सदस्य देशों से गैर बराबरी पूर्ण सम्बन्ध रखते थे। 'अंतर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन' के नाम पर कुछ देशों को किन्हीं विशिष्ट वस्तुओं के उत्पादन तक ही सीमित रख दिया जाता था। अक्सर ऐसे देश सोवियत संघ के लिए प्राकृतिक संसाधनों, कच्चेमालों, कृषि उत्पादों के सस्ते निर्यातक थे। कॉमेकॉन 1956 से 1991 में सोवियत संघ के विघटन तक कायम था। उत्तरी कोरिया ने 1963 में भी इसका सदस्य बनने से इंकार कर दिया था। 1963 में सोवियत संघ ने अस्थायी तौर पर उत्तरी कोरिया को आर्थिक व सैनिक मदद रोक दी थी। यही वह समय है जब अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट आंदोलन में खुला विभाजन हो गया था। जूछे विचार को तब से, विशेषकर, किम इल-सुंग दोहराने लगे थे। सोवियत संघ ने उत्तरी कोरिया को अपने पक्ष में करने के लिए आर्थिक व सैनिक मदद पर रोक लगा कर इस तरह के दबाव बनाने की कोशिश की थी।

अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट आंदोलन की एकजुटता के लिए किम इल-सुंग ने सैद्धान्तिक विचारधारात्मक एकता के स्थान पर बेहद 'व्यावहारिक', यात्रिक, रूपवादी रास्ता रखा। इस रास्ते में तथाकथित समाजवादी खेमे के देशों को 'राजनीतिक स्वतंत्रता' के या जूछे के सिद्धान्त के हिसाब से एक-दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना था। साम्राज्यवाद का विरोध और राष्ट्रीय मुक्ति के संघर्षों व मजदूर आंदोलनों का समर्थन करते हुए समाजवाद और साम्यवाद की ओर बढ़ना था। किम इल-सुंग इस काल में लगातार ही समाजवादी खेमे की एकता पर जोर देते रहे थे। वे न तो सोवियत संघ के साथ थे और न ही समाजवादी चीन के साथ। वे तो समाजवादी खेमे के साथ थे।

'महान बहस' और 'सांस्कृतिक क्रांति' से परिचित हर कम्युनिस्ट जानता है कि उस दौरान कई बुनियादी सवाल उठ खड़े हुए थे। जिसमें 'मध्यम मार्ग', 'समझौते' या 'दखलन्दाजी व राजनीतिक स्वतंत्रता' जैसे रास्ते व फिकरों का कोई स्थान नहीं था।

संशोधनवादी जहां सर्वहारा तानाशाही को खत्म करके पूंजीवादी तानाशाही को पुनर्स्थापित करना चाहते थे व कर रहे थे, वहीं कम्युनिस्ट क्रांतिकारी इस बात को स्थापित कर रहे थे कि समाजवाद में वर्ग, वर्ग-संघर्ष, वर्ग-अंतर्विरोध क्योंकि मौजूद रहते हैं इसलिए समाजवाद को बनाये रखने, साम्यवाद की ओर बढ़ने के लिए यह आवश्यक है कि सर्वहारा की तानाशाही को सुदृढ़ किया जाए। माओ के नेतृत्व में कम्युनिस्ट इस बात को स्थापित कर रहे थे कि 'शान्तिपूर्ण संक्रमण', 'शान्तिपूर्ण प्रतियोगिता', 'शांतिपूर्ण सह अस्तित्व' घोर संशोधनवादी विचार हैं। पूंजीवाद और साम्राज्यवाद की सेवा करने वाले विचार हैं। 'सारी जनता का राज्य' और 'सारी जनता की पार्टी' का अर्थ मात्र इतना ही है कि एक समाजवादी राज्य को पूंजीवादी राज्य तथा सर्वहारा की पार्टी को पूंजीवादी पार्टी में तब्दील कर दिया जाय। वर्ग, वर्ग अंतर्विरोध, वर्ग-संघर्ष से इंकार करने के बाद समाजवादी समाज को भले ही साम्यवादी समाज घोषित कर दिया जाए, उससे उसके साम्यवादी होने के स्थान पर पूंजीवादी राज्य में तब्दील होने का प्रमाण मिलता है। अब समाजवादी खेमे में एकता संशोधनवादी विचारधारा की निर्णायक शिकस्त के बाद ही हो सकती थी।

किम इल-सुंग अपनी अवस्थिति को इस समय अक्सर ही सबसे क्रांतिकारी दिशा के रूप में प्रस्तुत करते थे। अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट आंदोलन की चर्चा करने पर वे बिना नाम लिए हुए कहते थे कि कम्युनिस्ट आंदोलन में 'वामपंथी' और 'दक्षिणपंथी' भटकाव पैदा हो गये हैं।

किम इल सुंग ने चीन में जारी सांस्कृतिक क्रांति को चीन का आंतरिक मामला घोषित कर दिया था और कोई पक्ष नहीं लिया। परन्तु 1968 में चीन में सांस्कृतिक क्रांति के दौरान जब रेड गार्ड्स नें किम इल-सुंग की खुलेआम और नाम लेकर आलोचना शुरू कर दी और बीजिंग के अखबार में एक लेख 'आज के कोरियाई संशोधनवादी गुट' (The Korean Revisionist Clique of Today) छपा तो किम इल-सुंग ने इस बात को सुनिश्चित किया कि माओ के उद्धरणों वाली पुस्तक जो कि कम्युनिस्टों के बीच लाल किताब (Red Book) के नाम से जानी जाती है, कोरिया में न बंटे।

इस घटना के बाद चीन और उत्तरी कोरिया के आपसी सम्बन्धों में खटास पैदा हो गयी जिसे दूर करने के लिए चाऊ एन लाई ने 1970 में उत्तरी कोरिया की यात्रा की थी।

इस बात में कोई संदेह नहीं कि उत्तरी कोरिया ने साठ व सत्तर के दशक में राजनीतिक स्वतंत्रता बना कर रखी हुई थी। उसने सोवियत संघ और चीन के बीच 1969 में सीमा विवाद होने पर किसी का पक्ष नहीं लिया यद्यपि 1968 में सोवियत संघ के चेकोस्लोवाकिया पर हमला करने के साथ उसके सामाजिक साम्राज्यवादी होने पर कोई संदेह नहीं रह गया था। लेकिन 'राजनीतिक स्वतंत्रता' की भी अपनी पक्षधरता होती है।

1972 में सोवियत संशोधनवादियों ने किम इल-सुंग के साठवे जन्मदिवस के अवसर पर उन्हें 'आर्डर आफ लेनिन' से सम्मानित किया। ब्रेझनेव द्वारा किम इल-सुंग को 'ऑर्डर ऑफ लेनिन' देना और किम इल-सुंग का इस सम्मान को स्वीकारना कई अनकही बातों को स्वयं स्पष्ट कर देता है।

वैसे किम इल-सुंग के लिए समाजवादी खेमा हमेशा ही बना रहा। 1989-91 की घटनाओं की किम इल-सुंग की प्रस्तुति यह थी कि क्योंकि सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के देशों ने जूछे विचारधारा को नहीं अपनाया था इसलिए वहां पर समाजवादी व्यवस्था का खात्मा हुआ और पूंजीवाद की पुनर्स्थापना हुई।

किम इल-सुंग यद्यपि यह दावा करते थे कि उनका समाजवादी निर्माण का रास्ता किसी भी देश की नकल नहीं है तथा कोरियाई परिस्थिति और अनुभव से उपजा है तथापि यह स्वतंत्र रास्ता उतना स्वतंत्र तथा उतना अनूठा नहीं था जितने का दावा किया जाता था। कोरियाई समाजवाद के निर्माण में लगभग वही मॉडल अपनाया गया था जिसके आधार पर सोवियत संघ में स्तालिन के समय समाजवाद का निर्माण हुआ। इसी तरह समाजवादी क्रांति के दौरान धनी किसानों, राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग तथा मध्यम संस्तरों को वर्ग के बतौर खत्म करने के लिए जो तरीका उत्तरी कोरिया ने अपनाया था वह भी कोई अनूठा नहीं था। चीन में भी इसी तरीके से शोषक वर्गों को समाप्त किया गया था। यहां तक कि सर्वहारा वर्ग के सत्ता पर कब्जा करने के बाद इन वर्गों से निपटने की यह नीति मार्क्स, एंगेल्स, व लेनिन की रचनाओं में मौजूद है। किम इल-सुंग का दावा इतना ही ठीक है कि सोवियत संघ और अन्य समाजवादी देशों की तरह आम जनता की पहल कदमी खोलने के लिए विशिष्ट कोरियाई नाम वाले महान जन आंदोलन किये गये थे। छोलिमा आंदोलन, जिसका जिक्र पहले किया जा चुका है तथा 1960 के सहकारिता आंदोलन के दौरान की छोंडन्सान-री भावना तथा छोंडन्सान-री प्रणाली इनमें प्रमुख हैं।

समाजवाद से साम्यवाद की ओर कूच करने अथवा साम्यवाद की अवस्था तक पहुंचने के लिए किम इल-सुंग का मुख्य और मुख्यतः जोर उत्पादक शक्तियों के विकास पर रहता था। उत्पादक शक्तियों के विकास के जरिये वह स्थिति हासिल की जानी थी जिसके जरिये कम्युनिस्ट वितरण प्रणाली लागू हो सके।

किम इल-सुंग के कुछ पुराने वक्तव्यों से यह बात बहुत स्पष्ट हो जाती है कि वे विचार के पुराने धरातल पर ही खड़े थे। 8 फरवरी 1960 को उन्होंने कहा,

> "समाजवाद से कम्युनिज्म में संक्रमण के लिए उत्पादक शक्ति के और अधिक विकास की, अधिकाधिक परिमाण में चीजों के उत्पादन की, और जनता की चेतना के कम्युनिस्ट पुनः संस्कार की भी आवश्यकता होती है। कम्युनिज्म स्थापित करने के लिए चीजों की इतनी बहुतायत होनी चाहिए कि जनता की इच्छा पूर्णतया तुष्ट की जा सके। अगर चीजों की बहुतायत होनी है तो प्रविधि का और अधिक विकास किया जाना चाहिए और श्रम की उत्पादकता और ऊंची की जानी चाहिए ताकि उपभोग की वस्तुओं को आपार बहुतायत से पैदा किया जा सके।
>
> " कम्युनिस्ट समाज में सारे उत्पादन का यंत्रीकरण स्वचालित हो जाता है और कुशल तथा अकुशल श्रम और मानसिक तथा शारीरिक श्रम के बीच भेद समाप्त हो जाता है। इसलिए तब हर एक को उसकी आवश्यकतानुसार समानता से चीजें बांट देना और जो भी वह चाहे, दे देना सम्भव हो जाता है।
>
> " किंतु समाजवादी समाज में अभी उत्पादक शक्तियां इतनी विकसित नहीं होती हैं। चूंकि यंत्रीकरण अभी पूरी तरह लागू नहीं हुआ है, इसलिए श्रम में अनेक भेद रह जाते हैं।" (किम इल-सुंग, 'समाजवादी कृषि के सही प्रबंध के सम्बन्ध में', कांङसो काउंटी में छोंडन्सान-री के पार्टी के संगठन के आम सदस्यों की बैठक में दिया गया भाषण, प्रष्ठ-142, 'समाजवादी ग्रामीण प्रश्न के सम्बन्ध में,' वही)

इसी तरह की बातें किम इल-सुंग ने अन्य स्थानों पर की हैं। यहां से जो लाइन निकलती है वह यह कि तीव्र गति से तकनीक क्रांति की जाय। परम्परागत अर्थ वाली सांस्कृतिक क्रांति तथा विचारधारात्मक क्रांति के जरिये तकनीकी क्रांति को तीव्र करना, उत्पादक शक्तियों का तीव्र गति से विकास करना ताकि समाजवाद शीघ्र से शीघ्र साम्यवाद की अवस्था में दाखिल हो सके।

साफ सी बात किम इल-सुंग समाज में वर्ग संघर्ष, वर्ग भेद को पुराने समाज के अवशेषों के रूप में ही देखते हैं। 1972 के पहले तक तो वे लेनिन द्वारा इन संदर्भों में कही गयी बातों का जिक्र भी करते हैं परन्तु बाद के वर्षों में ये हवाले क्रमशः कम होते चले गये।

यहीं पर एक अन्य बात, 1972 के पहले किम इल-सुंग कोरियाई क्रांति में सोवियत संघ की 1945 तथा उसके बाद चीन की भूमिका के योगदान की चर्चा किया करते थे परन्तु 1963 के बाद यह सिलसिला लगातार कम होता चला गया। 1974 के बाद तो मात्र किम इल-सुंग का ही कोरिया की मुक्ति, जनवादी और समाजवादी क्रांति में योगदान था। वे और उनका जूछे विचार ही वह शक्ति थे जिनसे कोरिया के औपनिवेशिक अर्द्ध सांमती समाज को समाजवादी राज्य में तब्दील किया गया था। पहले अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्टों की कोरिया में निभायी गयी भूमिका पर चुप्पी साधी गयी और 1974 के बाद एक समय तो ऐसा आ गया जब मार्क्सवाद-लेनिनवाद की चर्चा औपचारिक तौर पर भी बंद हो गयी। और फिर पूरे समाज का किम इल-सुंगीकरण कर दिया गया।

कोरियाई समाजवाद ने जो रास्ता पकड़ा था उसमें पहले पहल संकट के चिह्न 1968 में पैदा होने शुरू हो गये थे। पहली सात वर्षीय योजना जो कि 1961 से शुरू हुई थी, उसे अपने लक्ष्य पूरे करने के लिए तीन वर्ष और बढ़ाना पड़ा था। सोवियत संघ-चीन विवाद तथा अमेरिकी साम्राज्यवाद की आक्रमणकारी नीतियों के कारण सेना और सुरक्षा के लिए हथियारों पर जोर देने का प्रभाव भी इस योजना पर पड़ा था। परन्तु ये ऐसे कारण नहीं थे जो कि बहुत नये हों क्योंकि अमेरिकी साम्राज्यवाद की सैनिक उपस्थिति दक्षिण कोरिया में सन् 1945 से ही बनी हुई और उत्तरी कोरियाई समाज को तब से ही युद्ध की स्थिति में रहना पड़ रहा था। '53 में हुआ युद्ध विराम आज तक भी किसी स्थायी शान्ति सन्धि में तब्दील नहीं हो सका है, इसके मूल कारण कोरियाई समाजवाद की दिशा में थे। कोरियाई समाजवाद में समाजवादी उत्पादन सम्बंध उस स्तर पर कभी नहीं पहुंचे जिस स्तर पर सोवियत संघ अथवा समाजवादी चीन में पहुंचे थे। उत्तरी कोरिया में कृषि कभी भी सहकारीकरण के स्तर से आगे नहीं बढ़ सकी। असल में कृषि में निम्न समाजवादी उत्पादन सम्बंध ही बने रहे।

उत्तरी कोरिया में जारी समाजवादी प्रयोगों तथा चीन में किये जा रहे समाजवादी प्रयोगों की आपस में तुलना की जाय तो दोनों ही देशों में पूंजीवादी कार्यदिशा और समाजवादी कार्यदिशा का फर्क एकदम सामने आ जाता है।

एक बड़ा अच्छा उदाहरण है जो दोनों ही देशों में अलग-अलग ढंग से किया गया। कोरिया में सहकारी किसानों को साग सब्जी उगाने के लिए और इसी तरह चीन में जन-कम्यून के सदस्यों को भी निजी जरूरत को पूरा करने के लिए 'निजी प्लॉट' दिये गये। इसके पीछे क्या सोच काम कर रही थी पहले किम इल-सुंग से फिर चीनी कम्युनिस्टों से सुनते हैं।

किम इल-सुंग लिखते हैं,

> "हमारी पार्टी ने इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए इस बात पर ध्यान दिया कि सहकारी किसानों को साग-सब्जी उगाने के लिए जमीन के छोटे-छोटे निजी प्लॉट दिये जायें। उनके विचारों मे बची-खुची स्वार्थ की भावना को दूर करने के लिए उनकी वैचारिक शिक्षा को प्रभावकारी बनाना सबसे ज्यादा जरूरी है। यह ठीक बात है, मगर स्वार्थपरता दूर करने के लिए केवल वैचारिक शिक्षा पर्याप्त नहीं है। स्वार्थपरता को मिटाने के लिए यह जरूरी है कि वैचारिक शिक्षा को प्रभावकारी बनाते हुए हम ऐसी भौतिक परिस्थितियां न पैदा करें जिसमें इसके पनपने की गुंजाइश हो। अगर सहकारी फार्मों के किसानों को साग-सब्जी पैदा करने के लिए बड़े प्लॉट दे दिये जायें तो सहकारी फार्मों के काम में सक्रिय रूप से भाग लेने की जगह उनकी दिलचस्पी सिर्फ अपने इन निजी प्लॉटों में हो सकती है और इस प्रकार उनकी स्वार्थपरता भी बढ़ेगी। इसलिए हमने जान बूझ कर अपने किसानों को साग-सब्जी उगाने के लिए छोटे-छोटे प्लॉट दिये ताकि अहंकार और छोटे मालिक की मनोवृत्ति से वे अपने को मुक्त कर सकें, सामूहिक भावना विकसित कर सकें और सहकारी फार्मों पर सामूहिक श्रम में उत्साह के साथ भाग ले सकें। (किम इल-सुंग, जनवादी और समाजवादी क्रांतियों के कुछ अनुभव, 11 अक्टूबर 1969, पार्टी और राज्य कार्यकर्ताओं के बीच भाषण; पृष्ठ- 284, पैरा-4, वही)

चीन में सांस्कृतिक क्रांति के दौरान लिखी गयी पुस्तक 'राजनीतिक अर्थशास्त्र के मूलभूत सिद्धांत' कहती है,

> "यदि जन-कम्यून की सामूहिक अर्थव्यवस्था का विकास और प्रधानता सुनिश्चित रहे, और इसका पूरा ध्यान रखा जाए, तो कम्यून के सदस्यों को खाली समय तथा छुट्टियों में छोटे-छोटे जमीन के टुकड़ों पर अपनी निजी जरूरत की चीजें उगाने तथा सीमित पैमाने पर घरेलू उत्पादन करने की अनुमति और प्रोत्साहन दिया जाता है। निजी जमीन के टुकड़े रखना और उस पर खेती करना तथा छोटे-मोटे पारिवारिक व्यवसाय चलाना छोटे पैमाने की निजी अर्थव्यवस्था के ही अवशेष हैं। लेकिन समाजवाद के तहत ये गतिविधियां सामूहिक स्वामित्व पर आधारित समाजवादी अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई और उसके अधीन होती हैं। समाजवादी संक्रमण के दौरान कुछ समय तक खेती और घरेलू व्यवसाय ग्रामीण क्षेत्र में श्रमशक्ति को और ज्यादा उपयोग में लाये जाने, सामाजिक उत्पाद को बढ़ाने, कम्यून सदस्यों का जीवन स्तर सुधारने तथा ग्रामीण मेलों में उपलब्ध वस्तुओं की विविधता व मात्रा बढ़ाने में एक भूमिका अदा करते हैं। लेकिन साथ ही, छोटे पैमाने के निजी स्वामित्व की प्रणाली के ऐसे अवशेष उस मिट्टी का काम करते हैं जिनमें पूंजीवाद पनपता है, और इसीलिए उनकी नकारात्मक भूमिका पर अंकुश रखने के लिए नेतृत्व को मजबूत बनाया जाना चाहिए।
>
> (अध्याय-13, 'सार्वजनिक स्वामित्व की समाजवादी प्रणाली समाजवादी उत्पादन सम्बंधों की बुनियाद होती है; राजनीतिक अर्थशास्त्र के मूलभूत सिद्धान्त, खण्ड-दो, पृष्ठ-43, पैरा-2, हिन्दी अनुवाद, राहुल फाउण्डेशन, लखनऊ)

बातें काफी स्पष्ट हैं। किम इल-सुंग की बात का सार यह है कि वे सहकारी फार्म के किसानों को छोटे-छोटे निजी प्लाट इसलिए देते हैं ताकि किसान अपने आपको छोटे मालिक की मनोवृत्ति से मुक्त कर सकें। चीन के कम्युनिस्टों ने इसके नितान्त भिन्न कारण दिये हैं जिसमें साफ तौर पर यह बात भी दर्ज है कि छोटे पैमाने के निजी स्वामित्व की प्रणाली पूंजीवाद के लिए उपजाऊ भूमि का कार्य करती है।

उत्तरी कोरिया के सहकारी फार्मों तथा चीन के जन कम्यूनों में स्वामित्व प्रणाली की दृष्टि से भी बहुत बड़ा फर्क है। जन कम्यूनों में सामूहिक स्वामित्व को निर्धारित करने के लिए त्रिस्तरीय (उत्पादन टीम, ब्रिगेड व कम्यून) प्रणाली थी जबकि उत्तरी कोरिया के अधिकांश सहकारी फार्म स्वामित्व की दृष्टि से अभी भी निम्न स्तर पर खड़े थे। सामूहिकीकरण और पूरी जनता के स्वामित्व वाली प्रणाली तक पहुंचने की एक लम्बी यात्रा उसे अभी करनी थी। उत्तरी कोरिया के 1972 के संविधान में जब समाजवादी उपलब्धियों को संवैधानिक रूप से सुदृढ़ करने की घोषणा की गयी थी तब भी उत्तरी कोरिया में स्वामित्व प्रणाली के दो रूपों राज्य की सम्पत्ति तथा सहकारी सम्पत्ति की घोषणा की गयी। साथ ही यह घोषणा की गयी कि कोरियाई समाज में वर्गीय अंतर्विरोध का दुश्मनाना चरित्र, व वर्गीय शोषण खत्म हो गया है।

1972 में जब किम इल-सुंग व कोरियाई कम्युनिस्ट समाजवादी उपलब्धियों को संवैधानिक रूप प्रदान कर रहे थे तब एक दूसरी प्रक्रिया अपनी निश्चित गति और परिणाम की ओर अग्रसर हो रही थी।

इस दूसरी प्रक्रिया के दो हिस्से थे। पहले हिस्से के तौर पर किम इल सुंग के वैचारिक अवसरवाद ने धीमे-धीमे करके एक निश्चित आकार ग्रहण कर लिया था। जूछे शब्द जो 1955 में मात्र इस बात का परिचायक था कि किसी समाजवादी देश को आत्मनिर्भरता की नीति का पालन करना चाहिये, जो कि एक सामान्य और जरूरी बात थी, 1963 में जूछे विचार का स्तर हासिल करती है। कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों तथा संशोधनवादियों के बीच चले संघर्ष में यह विचार वैचारिक अवसरवाद का प्रतीक बन गया। 1968 से 1974 का काल वह है जिसमें जूछे विचार विचारधारा के स्तर पर पहुंच जाता है। विचारधारा के स्तर पर पहुंचते जाने के साथ मार्क्सवाद-लेनिनवाद से इसकी दूरी बढ़ती जाती है और यह एक संशोधनवादी विचारधारा में तब्दील हो जाता है। यही वह काल है जिसमें उत्तरी कोरियाई समाज के समाजवादी उत्पादन सम्बंधों को निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर बढ़ना चाहिये था, पर वे निम्न स्तर पर ही बने रहते हैं। निम्न समाजवादी उत्पादन सम्बंधों वाला समाजवादी समाज क्रमशः एक राजकीय-पूंजीवादी समाज में तब्दील होता जाता है। समाजवादी सम्पत्ति के रूप तो कायम रहते हैं परन्तु उनका अंतर्य बदल चुका होता है।

अंततः स्थिति वहां पहुंच जाती है जहां एक निम्न समाजवादी उत्पादन सम्बंधों वाला समाजवादी देश राजकीय पूंजीवादी समाज में तब्दील हो जाता है। पूंजीवादी पुनर्स्थापना हो जाती है।

वैचारिक स्तर पर जूछे विचार विचारधारा के स्तर पर पहुंच जाता है और इसे जूछे विचारधारा के साथ-साथ किम इल-सुंगवाद का नाम 19 फरवरी 1974 को पार्टी की सेण्ट्रल कमेटी के सेक्रेटरी किम जॉग-इल द्वारा दे दिया जाता है। किम जांग-इल को 1973 में सेण्ट्रल कमेटी का सेक्रेटरी बनाया जाता है।

19 फरवरी 1974 के किम जांग-इल के भाषण के कुछ हिस्सों को हम उद्धृत कर रहे हैं। किम जॉग-इल के भाषण का शीर्षक है, 'हमारी पार्टी के विचारधारात्मक कार्य का तात्कालिक कार्यभार पूरे समाज के किम इल-सुंगीकरण की ओर लक्षित होने के बारे में' (On The Immidiated Tasks in Party Ideological Work Aimed at Kim Il Sungizing The Whole of Society) है। किम जॉग-इल का कहना है,

> "हम एक नये युग, जूछे युग, में रह रहे हैं जो कि इसके पूर्व के कालों से बुनियादी तौर पर भिन्न है।
>
> "हमारा युग, जूछे का युग, कुछ और भी होने से पहले एक ऐसा नया ऐतिहासिक युग है जिसमें व्यापक जन समुदाय अपने खुद के भाग्य के मालिक होने के तौर पर, इतिहास में पहली बार विश्व के मालिक के बतौर अपनी शुरूआत कर चुके हैं।
>
> "जूछे का युग पूर्णतया एक नया युग है जब व्यापक जन समुदाय अपने खुद के भाग्य का स्वतंत्र और सृजनात्मक रूप से निर्माण करते हैं तथा इतिहास को विकसित करते हैं। ...
>
> "किम इल-सुंगवाद एक नया मौलिक, क्रांति के बारे में एक महान विचार है जो जूछे युग की आवश्यकताओं को प्रतिबिम्बित करते हुए अस्तित्व में आया है।"...
>
> "संक्षेप में किम इल-सुंगवाद जूछे के विचार, सिद्धान्त और तरीके की एक व्यवस्था है। दूसरे शब्दों में यह, की क्रांति और निर्माण के सिद्धान्त और तरीके की एक व्यापक व्यवस्था है जो इस विचार द्वारा प्रतिपादित की गयी है।
>
> "क्रांति के पूर्ववर्ती मजदूर वर्ग के सिद्धांतों से अलग करने वाले किम इल-सुंगवाद का विशिष्ट लक्षण इस तथ्य में निहित है कि इसके पास क्रांतिकारी सिद्धान्त और नेतृत्व के तरीके की एकीकृत व्यवस्था है और इसकी आत्मा के तौर पर जूछे विचार हैं। किम इल-सुगवाद हमारे युग, जूछे युग की क्रांति के लिए सही नेतृत्वकारी उसूल, सिद्धान्त और नेतृत्व के तरीके उपलब्ध कराता है।...
>
> "समूचे समाज के किम इल-सुंगीकरण से क्या अर्थ है? इसका मतलब राष्ट्रपति के किम इल-सुंगवाद के महान क्रांतिकारी विचार को अपने एक मात्र पथप्रदर्शक विचार के बतौर क्रांति को जारी रखना, किम इल-सुंगवाद के आधार पर कम्युनिज्म का निर्माण करना और उसे पूरा करना है।...
>
> "दूसरे शब्दों में समूचे समाज का किम इल-सुंगीकरण करने का उद्देश्य अपने सभी सदस्यों को राष्ट्रपति के प्रति असीम वफादार किम इल-सुंगवादियों को प्रशिक्षित करना, समाज को किम इल-सुंगवाद की आवश्यकता के मुताबिक पूर्णतया रूपान्तरित करना और कम्युनिज्म के विचारधारात्मक किलों को फतह करना है।"
>
> **(Great Leader Kim Jong IL (II)s Biography Tak Jin, Kim Gang IL, pak Hong Je, Sorinsha, Tokyo, Japan, 1986 Page-22,23,25)**

इन उद्धरणों में कही गयी बातों का अर्थ किसी मार्क्सवादी-लेनिनवादी के लिए इतना स्पष्ट है कि हम किसी किस्म की व्याख्या की आवश्यकता नहीं समझते हैं। 1974 आते-आते कोरिया की मजदूर पार्टी एक संशोधनवादी पार्टी में तब्दील हो चुकी है। यहां जनवादी केन्द्रीयता का कोई स्थान नहीं है। व्यक्ति किम इल-सुंग और उनका पुत्र सबसे ऊपर है और सबसे सही है। उनके प्रति वफादारी, उनके पीछे लामबंदी ही क्रांतिकारिता और कम्युनिज्म है।

> "पार्टी बैठकों में किसी भी अकेले व्यक्ति को छा जाने की (Run a one man show) इजाजत नहीं दी जानी चाहिए ...पार्टी के सांगठनिक जीवन से सम्बन्धित महत्वपूर्ण मसलों में से एक पार्टी भावना को मजबूत करना है... संक्षेप में पार्टी भावना का मतलब नेता और पार्टी के प्रति वफादारी है... पार्टी की केन्द्रीय कमेटी के सदस्य महासचिव के इर्द-गिर्द एकमन और एक इच्छा शक्ति के साथ दृढ़ता से एकताबद्ध होने चाहिए। इस तरीके से यदि महासचिव 'A' कहता है तो वे 'A' कहेंगे यदि वह 'B' कहता है तो 'B' कहेंगे। उनको एक ही बात बोलनी चाहिये और एक साथ कार्य करना चाहिये।
>
> (N.Steinmayr की पुस्तिका के Page-41 में किम इल सुंग का उद्धरण, पूर्व में उद्धृत)

उपरोक्त उद्धरण किम इल-सुंग के 17 फरवरी 1975 के उस भाषण का हिस्सा है जो उन्होंने पांचवीं केन्द्रीय कमेटी के दसवे प्लेनम में दिया था। किम इल-सुंग अपने बेटे को क्रमशः स्थापित करते जा रहे थे। पहले किम इल-सुंग की देव प्रतिमा का निर्माण होता है और फिर उनके बेटे की। 'व्यक्ति पूजा' की न केवल मांग की जाती है बल्कि उसको संस्थागत रूप दे दिया जाता है। किम इल-सुंग के परिवार के सदस्य पार्टी, राज्य और सेना के महत्वपूर्ण पदों पर छा जाते हैं। इसी तरह कोरिया के इतिहास में भी किम इल-सुंग और उनके परिवार को महान क्रांतिकारी और देश भक्त के रूप में दर्ज किया जाता है। एक ऐसा वंश जिसके रक्त में ही क्रांतिकारिता और देश भक्ति है। पूरे समाज का किम इल-सुंगीकरण कर दिया जाता है। किम इल-सुंगवाद में मार्क्सवाद-लेनिनवाद के सभी बुनियादी विचारों और उनके आधार पर की गयी व्याख्याओं को पूर्णतया बदल दिया जाता है। इसमें वर्ग, वर्ग संघर्ष, समाजवाद, कम्युनिज्म, पार्टी, ऐतिहासिक भौतिकवाद दो लाइनों का संघर्ष सभी शामिल हैं।

किम जॉग-इल को 1980 में किम इल-सुंग का औपचारिक तौर पर उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाता है। 1980 के बाद क्रमशः पार्टी और सत्ता पर किम जॉग-इल की पकड़ मजबूत होती जाती है। 1994 में किम इल-सुंग की मृत्यु के बाद किम जॉग-इल वास्तव में उत्तरी कोरिया का शासक बन जाता है। लेकिन किम जॉग-इल राष्ट्रपति का पद नहीं सम्भालता है। वह पद तो आज भी किम इल-सुंग के पास ही है। वे शाश्वत राष्ट्रपति (Eternal President) हैं। वह राष्ट्र के आत्मिक पिता (Spiritual Father) हैं।

कुल मिलाकर जूछे विचारधारा या किम इल-सुंगवाद में राष्ट्रवाद, मार्क्सवाद-लेनिनवाद द्वारा पूंजीवाद-साम्राज्यवाद विरोधी आलोचना, माओ विचारधारा के कुछ रूपवादी तत्व, कन्फ्यूशियस की व्यक्ति पूजा व जीनियस की बातें, परिवारवाद, महान कोरियाई संस्कृति के पारिवारिक मूल्यों व जीवन मूल्यों का एक अजीब सम्मिश्रण है। जिसे पहले किम इल-सुंग और बाद मे उनके पुत्र किम जॉग-इल ने तैयार व विकसित किया। यह एक गैर सर्वहारा विचारधारा है।

उत्तरी कोरिया में पूंजीवाद की पुनर्स्थापना में सर्वप्रथम भूमिका कोरिया की मजदूर पार्टी और उसके नेतृत्व की गैर सर्वहारा विचारधारा और अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट आंदोलन में फूटे संघर्ष के समय गलत अवस्थितियां ग्रहण करने में है। इसके अलावा अन्य कारण पिछड़ी उत्पादक शक्तियां, एक ऐसे समाजवादी समाज जहां समाजवादी उत्पादन सम्बंध न केवल सुदृढ़ नहीं हुये बल्कि निम्न स्तर पर थे, पूरे समाज में मौजूद पिछड़ी मूल्य-मान्यताएं, निम्न पूंजीवादी प्रवृत्तियां, बाजार की मौजूदगी व माल का प्रचलन इत्यादि में हैं।

VI
राजकीय पूंजीवाद और खुला पूंजीवाद

उत्तरी कोरिया में राजकीय पूंजीवाद की स्थापना के बाद से अब तक के काल को मोटे तौर पर दो कालों या चरणों में बांटा जा सकता है। मोटे तौर पर इसलिए कि दूसरे काल की कई प्रक्रियाओं की शुरूआत पहले काल में हो चुकी थी। पहला काल, सत्तर के दशक के मध्य से नब्बे के दशक के मध्य तक माना जा सकता है। दूसरा काल, नब्बे के दशक के मध्य से अब तक का माना जाना चाहिये। पहले काल में मुख्यतः राजकीय पूंजीवाद कायम है जबकि दूसरे में खुले पूंजीवाद की ओर कदम उठाये गये।

पहला काल– इस काल को भी दो हिस्सों सत्तर के दशक के मध्य से 80 के दशक के मध्य तथा 80 के दशक के मध्य से 90 के दशक के मध्य, में बांट सकते हैं। पहला काल मोटे तौर पर राजकीय पूंजीवाद का काल है। अभी बड़े पैमाने पर आर्थिक सुधार नहीं लागू किये गये हैं। इस काल के पहले हिस्से में उत्तरी कोरिया की अर्थव्यवस्था ठीक हालत में है। जबकि दूसरे हिस्से में राजकीय पूंजीवादी व्यवस्था ठहराव की बुरी तरह शिकार होने लगती है तथा अर्थव्यवस्था क्रमशः गहरे संकट का शिकार हो जाती है।

पहले काल में हुए अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम ने भी उत्तरी कोरिया पर व्यापक प्रभाव डाला। 1976 में चीन में भी पूंजीवादी पुनर्स्थापना हो जाने से समाजवादी देशों के रूप में कोई देश नहीं बचा। चीन में भी राजकीय पूंजीवाद की स्थापना हो गयी। रंग बदलते ही चीनी

शासकों ने शीघ्र ही विभिन्न किस्म के पूंजीवादी सुधार लागू करने शुरू कर दिये और विस्तारवादी आकाक्षांओं नें नये समीकरणों की शुरूआत कोरिया प्रायद्वीप में भी कर दी। चीन के दक्षिण कोरिया, जापान, अमेरिका से सम्बंध नई जमीन पर बनने लगे। सोवियत संघ के उत्तरी कोरिया से सम्बंध प्रगाढ़ थे और वह उत्तरी कोरिया का मुख्य व्यापारिक साझेदार होने के साथ सैनिक सामग्रियों तथा तकनीक का भी मुख्य स्रोत था।

पहले गोर्बाचोव के सत्ता सम्भालने और फिर सोवियत संघ के विघटन ने उत्तरी कोरिया के शासकों के लिए भारी मुसीबत खड़ी कर दी। इधर दक्षिण कोरिया, जापान, अमेरिका के साथ चीन के नये सम्बंध मजबूती ग्रहण कर रहे थे। इसी तरह पूर्वी यूरोप के पूर्व समाजवादी देशों में हुए घटनाक्रम ने उत्तरी कोरिया के राजनीतिक व आर्थिक अलगाव को और बढ़ाने का काम किया।

पहले काल में किम इल-सुंग की मौजूदगी (पहले नेतृत्व में प्रत्यक्ष रूप में रहने, बाद में क्रमशः पृष्ठभूमि में चले जाने के बावजूद) उत्तरी कोरिया में राजनीतिक स्थिरता को बनाये रखती है परन्तु अस्सी के मध्य से ही अर्थव्यवस्था का संकट गहराने लगता है। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के व्यापक प्रभाव के चलते अर्थव्यवस्था बुरी तरह से संकटग्रस्त हो जाती है। 1993-94 में उत्तरी कोरिया के पहाड़ी इलाकों में पहला अकाल पड़ता है। कृषि के संकट में प्राकृतिक आपदाओं बाढ़ और सूखे की भी भूमिका होती है परंतु मुख्य भूमिका सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था के समग्र संकट की होती है। 1980 में किम इल-सुंग द्वारा किम जॉग-इल को अपना उत्तराधिकारी घोषित करने के बाद सत्ता क्रमशः किम जॉग-इल के हाथों में सिमटती जाती है। किम इल-सुंग का एक शानदार अतीत था जिसके कारण उनका एक बड़ा आभामण्डल तथा उत्तरी कोरिया के मेहनतकशों में गहरा सम्मान था। 1994 में किम इल-सुंग की मृत्यु होने पर उत्तरी कोरिया में शोक की लहर दौड़ गयी थी। किम इल-सुंग के नेतृत्व में हुए व्यापक परिवर्तन तथा उनकी जुझारू साम्राज्यवाद विरोधी राष्ट्रवादी छवि तथा कोरियाई एकीकरण के लिए उनके दृढ़ प्रयासों ने उन्हें जनता से कभी भी अलगाव में नहीं डाला, परन्तु किम जांग-इल के आभामण्डल में कुछ भी वास्तविक नहीं था, सब कुछ कृत्रिम था। उसकी सत्ता को वह स्वीकार्यता कभी हासिल नहीं हो सकती थी जो कि उसके पिता को हासिल थी। 1968 से ही उत्तरी कोरिया में सत्ता किम परिवार के हाथों में सिमटनी शुरू हो गयी थी। इस बात के पर्याप्त प्रमाण हैं कि इसका विरोध कोरिया की मजदूर पार्टी में प्रारम्भ हो गया था परंतु किम इल-सुंग की छवि तथा सत्ता पर उनकी मजबूत पकड़ से यह विरोध बहुत मुखरित नहीं हुआ। 1980 में इस विरोध ने मुखर स्वर पाये। संशोधनवादी पार्टियों और शोषक चरित्र वाली व्यवस्था के चरित्र के अनुरूप 1980 से खुले रूप में पनप रहे विरोध से किम जॉग-इल ने अपने तरीके से निपटा। जैसा कि पहले ही हम देख आये थे कि '74 से ही पार्टी में 'व्यक्ति पूजा' को संस्थागत रूप दे दिया गया था। किम जॉग-इल ने अपने पिता की छवि की आड़ में सभी विरोधियों को किनारे लगा दिया। ऐसी भी सूचनायें हैं कि कइयों की हत्यायें की गयीं (जिसमें अक्सर दुर्घटनाओं का हाथ होता था) तथा हजारों को जेल में डाला गया। इन सब में त्वरित गति किम इल सुंङ की मृत्यु के बाद आयी। 1998 में एक घटना के अनुसार किम जॉग-इल की हत्या का प्रयास किया गया। सेना तथा पुलिस में आपसी झड़पें हुई जिसके कारण प्योंगयांग में कर्फ्यू लगाना पड़ा।

सेना को अपनी पकड़ में बनाये रखने के लिए किम जॉग-इल ने अपने प्रयास 1980 से ही शुरू कर दिये थे। सेना मे किम परिवार के विरोधियों, सोवियत अथवा चीनी समर्थकों को बर्खास्त करने का चलन 1970 से प्रारम्भ था जिसने बाद में और गति पकड़ ली।

समाज में अपनी प्रतिक्रियावादी गिरफ्त को मजबूत करने के लिए जनता को तीन हिस्सों में (पार्टी कांग्रेस 1980) बांटा गया था। इसके अनुसार 25 फीसदी लोग केन्द्रक वर्ग (Core Class) 50 फीसदी लोग ढुलमुल वर्ग (Wavering Class) तथा 25 फीसदी लोग विरोधी वर्ग (Hostile Class) में थे। [इस वर्गीकरण को पाल फ्रेंच ने अपनी पुस्तक North Korea- The Paranoid Peninsula- A Modern History (Zed Books से प्रकाशित) में दिया है।] केन्द्रक वर्ग ही शासन में और इस शासन प्रणाली के मुख्य लाभों को उठाने वालों में है।

पहले काल के अंत में अर्थव्यवस्था के संकट की गहराई इस तथ्य से समझी जा सकती है कि 1992 में सरकार, कृषि और खाद्य संकट के कारण 'एक दिन में दो बार ही भोजन करो' (Eat two meals a day) अभियान चलाने को मजबूर हो जाती हैं। उत्तरी कोरिया की सरकार 1991 में संयुक्त राष्ट्र संघ के 'विश्व खाद्य कार्यक्रम (W.F.P.-U.N.) से सहायता की अपील करती है। उत्तरी कोरिया की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (P.D.S.) अस्सी के दशक के अंत से ही संकट में फंस रही थी तथा इसने आम जनता के राशन में पहले से ही कटौती शुरू कर दी थी। यह उस कोरिया की हालत थी जो कि एक समय खाद्यान्न के मामले में न केवल आत्मनिर्भर था बल्कि संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य व कृषि संगठन (F.A.O.) के अनुसार जिसकी धान की उपज प्रति हेक्टेअर दुनिया में सबसे अधिक थी।

पहले काल में दूसरी सात वर्षीय योजना 1978 में शुरू की गई थी। इससे पहले जैसा कि हम बता आये हैं कि उत्तरी कोरिया में पूंजीवादी पुनर्स्थापना के साथ अर्थव्यवस्था में संकट (सकल घरेलू उत्पाद की दर में धीमी वृद्धि या योजनाओं का पूरा न होना) के चिह्न 1968 से ही दिखाई देने लगे थे, 1971-76 की योजना को एक साल के लिए और बढ़ाना पड़ा था। इसी तरह 1978-84 की सात वर्षीय योजना को दो साल के लिए और इसलिए बढ़ाना पड़ा ताकि वो तय शुदा लक्ष्य हासिल कर सके। साफ था कि मेहनतकशों का क्रांतियों के काल का उत्साह और पहलकदमी समाप्त हो चुकी थी। उत्तरी कोरिया के पूंजीवादी पथगामी शासक योजनाओं के लक्ष्य या तो हासिल नहीं कर पा रहे थे या इसके लिए मेहनतकशों पर जिनसे उनका अलगाव बढ़ता जा रहा था, पर दबाव बना रहे थे। नौकरशाही और तानाशाही पूर्ण तरीकों से इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए जोर-जबरदस्ती कर रहे थे।

1971-1976 के बीच औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर 16.3% प्रति वर्ष थी लेकिन यह वृद्धि आगे के वर्षों में कायम नहीं रह सकी। अस्सी के दशक में सकल घरेलू उत्पाद की दर 2-3% रही। अस्सी के दशक के अन्तिम वर्ष अर्थव्यवस्था के गहरे संकट की ओर बढ़ने को दर्शा रहे थे। 1989 में सकल घरेलू उत्पाद की दर ऋणात्मक हो गयी और 1992 तक 3-5% की दर से गिरती गयी। ध्यान रखने वाली बात यह है कि यह वही काल है जब सोवियत संघ तथा पूर्वी यूरोप का संकट अपने चरम पर था। 1993 में उत्तरी कोरिया की सरकार ने औपचारिक तौर पर स्वीकारा कि वह तीसरी सात वर्षीय योजना (1987-93) के निर्धारित लक्ष्यों को हासिल नहीं कर सकी है।

दूसरा काल जुलाई 1994 में किम इल-सुंग की मृत्यु के बाद तीन साल तक कोरियाई परम्पराओं के अनुसार राष्ट्रीय शोक मनाया जाता है। किम इल-सुंग को 'शाश्वत राष्ट्रपति' घोषित कर दिया जाता है और इस दौरान किम जॉग-इल अपनी सत्ता को और सुदृढ़ करता है।

1994 में अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर क्लिंटन काबिज हुआ। अमेरिकी साम्राज्यवादियों की तरह कई यह अनुमान लगा रहे थे कि पूर्वी यूरोप और सोवियत संघ की तरह उत्तरी कोरिया की व्यवस्था अपने ढहने के कगार पर है। अर्थव्यवस्था की ऋणात्मक दर, कृषि और खाद्य संकट, ऊर्जा संकट, सोवियत संघ तथा पूर्वी यूरोप से होने वाले व्यापार और मदद का नुकसान, अकाल, किम इल-सुंग की मृत्यु आदि इस अनुमान को बल दे रहे थे। इसी अनुमान के बीच 1994 में क्लिंटन प्रशासन का किम जॉग-इल के साथ एक समझौता होता है जिसे 'मान्य समझौता ढांचा' (Agreed Frame work) के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के अनुसार उत्तरी कोरिया को अमेरिका के साथ राजनीतिक व आर्थिक सम्बंध सामान्य करने थे। इसके साथ-साथ उत्तरी कोरिया को अपने ग्रेफाइट नाभिकीय रियेक्टर तथा परमाणु हथियारों के प्रोग्राम को छोड़ना था। अमेरिका को इसकी एवज में कोरिया के ऊर्जा संकट को हल करने के लिए प्रतिवर्ष 3.3 मिलियन बैरल खनिज तेल देना था तथा 2003 तक उसे दो हल्के पानी वाले रियेक्टर (Light- water reactor) उपलब्ध कराने थे। लेकिन अमेरिका अपने किये गये वायदों से पीछे हट गया। उनके अनुमान के अनुसार जब उत्तरी कोरिया की व्यवस्था का पतन नहीं हुआ तो क्लिंटन के बाद राष्ट्रपति बने जॉर्ज बुश ने उसे 'शैतान ध्रुवी' (Axis of evils) में शामिल कर दिया। जॉर्ज बुश इराक की सद्दाम सरकार की तरह किम जांग-इल को सत्ताच्युत करने के लिए सैनिक मंसूबे बांधने लगा। उत्तरी कोरिया की भू-राजनैतिक स्थिति, दक्षिण कोरिया के शासकों तथा जनता के विरोध, इराक में मिली असफलता तथा विश्वव्यापी जन विरोध आदि कारणों ने अमेरिका के साम्राज्यवादी मंसूबों को पूरा नहीं होने दिया ।

उत्तरी कोरिया की 'जूछे विचारधारा' की सारी हवा नब्बे के दशक में निकलने लगी। उत्तरी कोरिया के शासकों ने एक के बाद एक ऐसे कदम उठाने शुरू किये जो उसकी अर्थव्यवस्था को परनिर्भरता की ओर बढ़ाते जा रहे हैं। इनमें विदेशी पूंजी निवेश को आमंत्रण, विशेष व्यापार व आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना, कीमत सुधार (price reform), मुद्रा अवमूल्यन व मुद्रा सुधार आदि प्रमुख हैं।

2001 में पार्टी के मुखपत्र रोडोंग सिनमुन (Rodong Sinmun) में एक लेख में किम जांग-इल ने घोषणा की,

> "चीजें उस तरह से नहीं रह गयी है जैसे कि वे 1960 में दशक में थी। इसलिए किसी को भी उस रास्ते को नहीं अपनाना चाहिये जिस पर अतीत में लोग चलते थे ... हमें लगातार इस बात के प्रयासों की आवश्यकता है कि उस परिदृश्य को जो कि अतीत में बना था, से नया परिदृश्य पैदा किया जाय ताकि नये युग की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके।"
>
> (पाल फ्रेंच, पृष्ठ-140, पैरा-2, वही)

किम जांग-इल के सामने दो ऐसे उदाहरण मौजूद थे जो कि उनकी दिशा को तय करने में मदद कर रहे थे। पहला उदाहरण सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के देशों का था जिनकी तथाकथित समाजवादी व्यवस्था का 1989-91 में पतन हो गया था। दूसरा उदाहरण चीन और क्यूबा का था। चीन का उदाहरण कोरिया के शासकों को लगातार आकर्षित करता रहा था। देंङ-श्याओ-पिंङ के चीनी विशेषताओं वाले समाजवाद' का रास्ता ही उनका रास्ता बनता जा रहा था। नब्बे के दशक तथा उसके बाद के समय में किम जांग-इल ने कई दफा चीन के 'विशेष आर्थिक क्षेत्रों' (SEZ) की यात्राएं की। किसी समय देंग श्याओं पिंग ने किम इल-सुंग से कहा था कि आर्थिक सुधार पश्चिम के लिए खिड़की का काम करेंगे तो किम इल-सुंग का जवाब था 'जब आप खिड़की खोलेंगे तो मक्खियां अंदर आ जायेंगी'। चीन की बढ़ती 'प्रगति' और हैसियत से प्रभावित किम इल-सुंग ने बाद में आर्थिक सुधारों की खिड़की खोल दी थी। किम जांग-इल ने नब्बे के दशक के पूवार्द्ध में उभरे गहरे आर्थिक संकट के बाद से सुधार की प्रक्रियाओं को तीव्र कर दिया था।

1984 में उत्तरी कोरिया ने एक संवैधानिक सुधार के जरिये विदेशियों के साथ संयुक्त उपक्रम लगाने की इजाजत दी। 1991 में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए उत्तरी कोरिया ने पहला 'मुक्त व्यापार और आर्थिक क्षेत्र' रूस-चीन-उत्तरी कोरिया की सीमा पर स्थित रेजेन-सोनवोंग स्थान में बनाया। 1996 में उत्तरी कोरिया के विदेशी आर्थिक को-आपरेशन (External Economic Co-Operation) के निर्देशक किम जांग-यू ने विदेशी निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए वाशिंगटन की यात्रा की। इसी तरह के प्रयास 1997 में डावोस में विश्व आर्थिक मंच (World Economic forum) की वार्षिक बैठक में किये गये। 1998 में 'लागत, कीमत, मुनाफे' (Costs, Prices and Profits) से सम्बन्धित विषयों के लिए संविधान में जगह बनायी गयी।

जुलाई 2002 में 'कीमतों में सुधार' (price reform) किये गये। इसी दौरान नवम्बर 2002 में उत्तरी कोरिया ने घोषणा की कि वह लेन देन तथा विदेशी मुद्रा भंडार के लिए डॉलर के स्थान पर यूरो को प्राथमिकता देगा। 1992 में इस बात को देखते हुए कि लोगों ने गुप-चुप ढंग से उत्तरी कोरियाई मुद्रा वोन (या कई दफा उत्तरी कोरियाई वोन-NKU) की जमा-खोरी कर रखी है तो मुद्रा सुधार किये गये।

छुपायी गयी मुद्रा को बाहर निकालने की इस कार्यवाही में बढ़ती मुद्रा स्फीति पर काबू पाना था। मुद्रा सुधारों की यह प्रक्रिया आगे भी जारी है। पूरे नब्बे के दशक तथा बाद में मुद्रा अवमूल्यन कई दफा करना पड़ा। कुल मिलाकर उत्तरी कोरिया के शासकों ने चीनी शासकों की राह पर नब्बे के दशक में पूरी तरह से पकड़ ली। लेकिन कई कारणों से (जिसमें उत्तरी कोरिया की राजनीतिक अवस्थितियां, साम्राज्यवादियों की उत्तरी कोरिया में पूंजी निवेश को लेकर शंकाएं, अवरचनागत सुविधाओं का अपर्याप्त विकास, विदेशी पूंजी के लिए और अधिक सुविधाएं) उत्तरी कोरिया के शासकों को चीनी शासकों के मुकाबले नाममात्र की सुविधाएं भी हासिल नहीं हुई।

'आत्म निर्भरता', 'स्वतंत्रता', जूछे विचारधारा, किम इल-सुंगवाद की परिणति समझने के लिए उत्तरी कोरिया के शासकों का शिनयूजू (sinuiju) का 'प्रयोग' काफी दिलचस्प है। 12 सितम्बर को सरकार ने एक अध्यादेश के जरिये शिनयूजू जो कि चीन की सीमा पर स्थित है (तथा चीन के डेनडोंग शहर के करीब है, डेनडोंग चीन के सफलतम विशेष आर्थिक क्षेत्रों में है) में विशेष प्रशासनिक क्षेत्र (Special Administrative Regeion-SAR) बनाने की घोषणा की। इस क्षेत्र की स्थिति राष्ट्र के भीतर राष्ट्र की है। डॉलर इसकी मुद्रा होनी है। अपनी विधायिका (Legislature), न्यायालय व पुलिस, अपना पासपोर्ट, और यहां तक कि इसका अपना झंडा भी होना है। कोरियन, चीनी तथा अंग्रेजी इसकी औपचारिक भाषायें होनी हैं। इस क्षेत्र को बनाने के लिए उत्तरी कोरिया के शासकों ने हजारों की संख्या में यहां के निवासियों को जबरदस्ती अन्य स्थानों पर जाने को मजबूर कर दिया है। शिनयूजू को उत्तरी कोरिया का शंघाई बनाने के लिए उत्तरी कोरिया के शासकों ने कोई कसर नहीं छोड़ी हुई है। इसके प्रशासन के लिए भारी संख्या में विदेशियों की नियुक्ति की गयी है। इसमें एक यूरोपियन को जज तथा एक अमेरिकन को पुलिस प्रमुख बनाया गया। हुंडई जो कि दक्षिणी कोरिया की एक बहुत बड़ी एकाधिकारी कम्पनी है के साथ उत्तरी कोरिया की सरकार को संयुक्त रूप से इसका विकास करना है। इस क्षेत्र का प्रशासनिक यांग-बिन नाम के एक ऐसे अप्रवासी चीनी को बनाया गया जो कि एक अरबपति है और एक समय चीन में भारी निवेश करने के कारण चीनी शासकों ने उसे हीरो के रूप में पेश किया था। यांग-बिन को 2002 में कर चोरी और भ्रष्टाचार के आरोप में चीनी अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार करने के बाद उत्तरी कोरिया के इस 'प्रयोग' पर ग्रहण लगना शुरू हुआ। उत्तरी कोरिया के अन्य 'विशेष आर्थिक क्षेत्रों' की तरह यहां भी अपेक्षित पूंजी निवेश न होने के कारण शिनयूजू शंघाई बनते-बनते रह गया है।

आर्थिक सुधारों में मिली असफलता, अर्थव्यवस्था का गहरा संकट, सामाजिक असंतोष, भारी पैमाने पर उत्तरी कोरिया से नागरिकों का भूख व बेरोजगारी के कारण चीन को पलायन, ऊर्जा का गहराता संकट, अमेरिकी व जापानी साम्राज्यवादियों का बढ़ता दबाव, अकाल व प्राकृतिक आपदाओं का बार-बार प्रकट होना आदि कारणों ने उत्तरी कोरिया के शासकों को दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है। उत्तरी कोरिया के प्रतिक्रियावादी शासकों ने जनता का दमन तथा उन्हें नियंत्रण में रखने के लिए भारी पैमाने पर हथियारों पर धन खर्च करना जारी रखा हुआ है। साम्राज्यवाद के वास्तविक खतरे तथा इस खतरे का दोहन करके उत्तरी कोरिया के शासकों ने जनता के ऊपर एक किस्म की सामाजिक-फासीवादी तानाशाही कायम की हुई है।

उपरोक्त कारण तथा अमेरिकी-जापानी साम्राज्यवादियों से सौदेबाजी करने के लिए उत्तरी कोरिया के शासकों ने पिछले कई वर्षों से 'मिलिट्री फर्स्ट' नीति अपनायी हुई है। इस नीति के तहत ही उत्तरी कोरिया ने मिसाइलों का परीक्षण तथा परमाणु विस्फोट किया है। 2002 में इसी नीति के दबाव के जरिये 6 देशों रूस, अमेरिका, जापान, चीन, दक्षिण कोरिया, उत्तरी कोरिया) की वार्ताएं शुरू हुई थी। उत्तरी कोरिया ने कुछ सुविधायें हासिल की थीं। परन्तु बढ़ते भीतरी व बाहरी दबाव ने 2006 में उसे मिसाइल व परमाणु परीक्षणों की ओर धकेला है। उत्तरी कोरिया के शासक साम्राज्यवादियों के आपसी अन्तर्विरोधों, चीन से निकटता, दक्षिण कोरिया की बढ़ी हुई आर्थिक व राजनीतिक हैसियत, जनता में एकीकरण की तीव्र इच्छा व साम्राज्यवाद के वास्तविक खतरे से जनता का भयदोहन आदि के जरिये अपने शासन को कायम रखे हुए हैं।

VII
कुछ जरूरी सबक

अल्पजीवी साबित हुए उत्तरी कोरियाई समाजवाद ने कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों को विगत इतिहास को समझने तथा भावी इतिहास का निर्माण करने के लिए कई महत्वपूर्ण सबक दिये हैं। सबसे पहले इसने सैद्धान्तिक व विचारधारात्मक प्रश्नों के महत्व को कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों के सामने फिर से प्रस्तुत किया है। इस अनुभव ने सिखाया है कि विचाराधारात्मक प्रश्नों में दिखाये गये किसी भी किस्म के विचलन, पलायन या अवसरवाद का नतीजा बहुत घातक होता है जो ऐसी पार्टियों, व्यक्तियों को अंततः संशोधनवाद के गहरे दलदल में धकेल देता है। जूछे विचारधारा की सम्पूर्ण यात्रा ने लेनिन के उस कथन की फिर पुष्टि की है जो उन्होंने लगभग एक सदी पूर्व दिया था। लेनिन ने कहा था,

> "... इसलिए **केवल ये रास्ते** ही रह जाते हैं: या तो बुर्जुआ विचारधारा को चुना जाय या समाजवादी विचारधारा को। बीच का कोई रास्ता नहीं है (क्योंकि मानवजाति ने कोई "तीसरी" विचारधारा पैदा नहीं की है, और इसके अलावा जो समाज वर्ग

विरोधों के कारण बंटा हुआ है, उसमें कोई गैर वर्गीय या वर्गोपरि विचारधारा कभी भी नहीं हो सकती)। अतएव समाजवादी विचारधारा के महत्व को **किसी भी** तरह कम करके आंकने, उससे **जरा भी मुंह** मोड़ने का मतलब बुर्जुआ विचारधारा को मजबूत करना होता है।" (लेनिन, क्या करें? पृष्ठ-58, प्रगति प्रकाशन मास्को, जोर मूल में)

उत्तरी कोरियाई समाजवाद के अनुभव ने महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति के सभी सबकों की पुष्टि की है। समाजवाद में हमेशा ही पूंजीवाद की पुनर्स्थापना का खतरा मौजूद रहता है। समाजवाद पूंजीवाद से साम्यवाद के बीच संक्रमण काल है। इस काल में सर्वहारा की न केवल तानाशाही कायम रहती है बल्कि सर्वहारा के क्रांतिकारी नेतृत्व में ही समाजवाद से साम्यवाद की अवस्था की ओर जाया जा सकता है। इस पूरे काल में सर्वहारा विश्व दृष्टिकोण पर दृढ़तापूर्वक खड़े रहते हुए तथा कई सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांतियां इस सुदीर्घ ऐतिहासिक अवधि अर्थात् समाजवाद में इस बात को सुनिश्चित कर सकती हैं कि पूंजीवाद की पुनर्स्थापना न हो। इस पूरे काल के दौरान यह आवश्यक है कि समाजवादी रूपों के बजाय अंतर्वस्तु पर सदा जोर दिया जाना चाहिये।

उत्तरी कोरियाई समाजवाद का अनुभव दिखाता है, जैसा कि हमने इस आलेख के एकदम शुरू में कहा था, कि किसी भी देश में क्रांति के विकास और विजय में अंतर्राष्ट्रीय सर्वहारा आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसी भी देश की क्रांति विश्व सर्वहारा क्रांति का अभिन्न हिस्सा है। अन्तर्राष्ट्रीयतावाद से किसी भी बड़े-छोटे किस्म का भटकाव अंततः राष्ट्रवाद या सारतः बुर्जुआ विचारधारा को अपनाना होता है। इसकी परिणति सर्वहारा के ध्येय से गद्दारी के रूप में ही सामने आ सकती है।

उत्तरी कोरिया की मजदूर पार्टी का विकास, उसका सर्वहारा पार्टी से बुर्जुआ पार्टी में तब्दील होना इस बात को दिखलाता है कि कम्युनिस्टों को सदा ही लेनिनवादी पार्टी उसूलों पर दृढ़ता पूर्वक खड़े होने की जरूरत है। पार्टी के भीतर पैदा होने वाली किसी भी किस्म की व्यक्तिपूजा, नौकरशाही, परिवारवाद, खुदगर्जी की प्रवृत्तियों के खिलाफ निरन्तर निर्मम विचारधारात्मक संघर्ष करना आवश्यक है।

परिशिष्ट

20 सूत्री कार्यक्रम

23 मार्च 1946 को उत्तरी कोरिया प्रोविजनल पीपुल्स कमेटी द्वारा पार्टी की राजनीतिक लाइन के आधार पर घोषित बीस सूत्री कार्यक्रमः

1- कोरिया के राजनीतिक व आर्थिक जीवन से जापानी साम्राज्यवादी शासन के सभी अवशेषों का पूर्णतया खात्मा;

2- देश के भीतर प्रतिक्रियावादियों और गैर जनवादी तत्वों के खिलाफ एक कठोर संघर्ष छेड़ना तथा फासिस्ट, गैर जनवादी राजनीतिक पार्टियों, संगठनों और व्यक्तियों की गतिविधियों को प्रतिबंधित करना;

3- पूरी जनता को अभिव्यक्ति, प्रेस, सभा करने तथा धर्म मानने की स्वतंत्रता देना। जनवादी पार्टियों, ट्रेड यूनियनों, किसान यूनियनों तथा अन्य जनवादी जन संगठनों को अपनी गतिविधि चलाने की स्वतंत्रता प्रदान करना;

4- सारी कोरियाई जनता के पीपुल्स कमेटी जो कि प्रशासनिक साधन तथा स्थानीय स्तर पर सभी कार्यो के लिए जिम्मेदार है, जिनको सार्विक, प्रत्यक्ष, बराबरी और गुप्त मतदान के आधार पर गठित होना है, के अधिकार तथा कर्त्तव्य को सुनिश्चित करना;

5- सभी नागरिकों को राजनीतिक व आर्थिक क्षेत्र में लिंग, धर्म, सम्पत्ति के आधार के बिना समान अधिकार प्रदान करना;

6- वैयक्तिकता, आवास तथा कानून द्वारा प्राप्त नागरिक की सम्पत्ति और व्यक्तिगत जायदाद की अनुल्लंघनीयता की गारण्टी करना;

7- जापानी साम्राज्यवादियों के समय से चले आ रहे सभी कानूनों और न्यायिक अंगों को समाप्त करना जिसके दुष्परिणामों से अब भी जनता कष्ट उठा रही है, जनवादी सिद्धान्तों के आधार पर निर्वाचित न्यायिक अंगों का निर्माण करना तथा सभी नागरिकों को समान कानूनी अधिकार प्रदान करना;

8- जनता के कल्याण में वृद्धि करने के लिए उद्योग, कृषि, परिवहन और व्यापार को विकसित करना;

9- बड़े उद्योगों, परिवहन सेवाओं, बैंकों, खानों और वनों का राष्ट्रीयकरण करना;

10- निजी दस्तकारी तथा व्यापार की स्वतंत्र गतिविधि की अनुमति व बढ़ावा देना;

11- जापानी नागरिकों, जापानी सरकार, देशद्रोहियों की और उन जमींदारों की जमीन को जब्त करना जो अब भी जमीन किराये पर देते हैं, काश्तकारी व्यवस्था को समाप्त करना और जब्त की गई सारी जमीन को किसानों में बांटना और उनकी सम्पत्ति बनाना। बिना किसी मुआवजे के सभी सिंचाई सुविधाओं को जब्त करना और उसे राजकीय नियंत्रण में लाना;

12- नित्य उपयोग की वस्तुओं के बाजार भाव को स्थिर रखना तथा सट्टेबाजों व सूदखोरों पर नियंत्रण लगाना;

13- एक समान, उचित टैक्स प्रणाली स्थापित करना तथा वर्धमान आयकर व्यवस्था लागू करना;

14- आठ घण्टे के कार्यदिवस को लागू करना और फैक्टरी तथा कार्यालय के कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन निर्धारित करना। 13 साल से कम उम्र के बच्चों को काम पर रखने से निषिद्ध करना तथा 13 से 16 साल तक के बच्चों के लिए 6 घण्टे का कार्यदिवस तय करना;

15- फैक्टरी तथा कार्यालय के कर्मचारियों के जीवन बीमा की योजना तथा मजदूरों और उद्यमियों के लिए बीमा व्यवस्था लागू करना;

16- सार्विक आवश्यक शिक्षा को लागू करना तथा प्राथमिक, माध्यमिक और विशिष्ट स्कूलों तथा कालेजों का व्यापक जाल बिछाना तथा उन्हें राजकीय व्यय पर चलाना। जन शिक्षा में लोक राज्य व्यवस्था की दिशा के अनुरूप सुधार करना;

17- राष्ट्रीय संस्कृति, विज्ञान और कला को सक्रिय रूप से विकसित करना तथा और अधिक थियेटरों, पुस्तकालयों, रेडियो प्रसारण केन्द्रों तथा सिनेमा गृहों का निर्माण करना;

18- सरकारी अंगों तथा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में कार्य करने वालों को प्रशिक्षित करने के लिए विशेष विद्यालयों की स्थापना करना;

19- वैज्ञानिकों और कलाकारों को उनके काम में प्रोत्साहन व सहायता देना;

20- राज्य संचालित अस्पतालों की संख्या बढ़ाना, महामारियों का नाश तथा गरीबों के लिए मुफ्त चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराना।

■■■